

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> भूमिहीन कृषि श्रमिकों की नवरात्रि...



वित्त विधेयक लोकसभा में पारित

निर्मला सीतारमण बोलीं- भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार

नई दिल्ली। वित्त विधेयक 2026 लोकसभा में 32 सरकारी संशोधनों को शामिल करने के बाद पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत तेजी से सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में सुधार किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का जिज्ञा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और लगातार आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम बनाने पर है, जिसके तहत ईमानदार करदाताओं के लिए प्रेरानिया कम की जा रही हैं। टैक्स प्रशासन को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।



वित्त मंत्री ने आम लोगों को राहत देने के लिए 17 जरूरी जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने का भी एलान किया। इससे इन दवाओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा।

छोटे करदाताओं के लिए भी प्रक्रिया को

आसान बनाया गया है। अब कम या शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट पाने के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे समय और जटिलता दोनों कम होंगे।

इसके अलावा, सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए सेस और सरचार्ज से अधिक राशि राज्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च की जा रही है, जिससे राज्यों को वित्तीय सहयोग मिलता है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई, किसान और सहकारी क्षेत्र रोजगार सृजन और उत्पादन के केंद्र में हैं, इसलिए सरकार इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। वित्त विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो इन सेक्टर के लिए तरलता बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेंगे।

पश्चिम एशिया संकट के बीच राजनाथ सिंह ने बीआरओ और सैन्य तैयारियों पर की अहम बैठक

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 मार्च को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर संसदीय परामर्श समिति की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन तैयारियों को मजबूत करने की पहलों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मैंने सीमा सड़क संगठन विषय पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा, अवसंरचना विकास और परिचालन तत्परता को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रही रणनीतिक पहलों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक और गहन विचार-विमर्श हुआ।

इससे एक दिन पहले, 24 मार्च को, रक्षा मंत्री ने हाल की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के मद्देनजर और भारत की रक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चीफ



ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष समीर कामत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, जो अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले व्यापार

मार्गों को बाधित कर दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ गई। जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजरायल और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिससे जलमार्ग में और अधिक व्यवधान उत्पन्न हुआ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ा।

31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद से होगा पूर्णतः मुक्त: विजय शर्मा



रायपुर। जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के समन्वित एवं सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पुनर्जागरण की

दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नारायणपुर विधायक एवं मंत्री श्री केदार कश्यप, जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंहदेव, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, पुलिस महानिदेशक एंटी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद, नक्सल उन्मूलन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी सीआरपीएफ, बस्तर कमिश्नर, आईजी सुंदरराज पी., बीजापुर के पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह द्वारा घोषित समय-सीमा के अनुरूप राज्य सरकार ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य किया, जिसका सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। इसी क्रम में हाल ही में डीकेजेडसी स्तर के नक्सली पापा राव ने अपने साथियों एवं हथियारों सहित पुनर्वास कर मुख्यधारा में वापसी की है। यह घटना न केवल सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि अब नक्सल संगठन का शीर्ष ढांचा भी कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि बस्तर के समाज ने भी खुले मन से इन पुनर्वासित लोगों को स्वीकार कर सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों में लगभग 3 हजार से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास किया है।

पब्लिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्वूलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम



कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्वूलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। मामला सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में था। बेंच ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदेमातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। ये दिशानिर्देश केवल प्रोटोकॉल हैं और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, या फिर उसके लिए गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इन सब बातों पर ध्यान देने वाले हैं। अदालत मुहम्मद सईद नूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें वह नोटिस दिखाइए जिसमें आपको राष्ट्रगान बजाने के लिए मजबूर किया गया है। आप एक स्कूल चलाते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि वह मान्यता प्राप्त है या नहीं।

ट्रंप नहीं हमारी शर्तों पर युद्ध खत्म होगा अमेरिका के सामने ईरान की पांच शर्तें

नईदिल्ली। ईरान ने युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा की है, लेकिन उसकी शर्तें उसे स्वीकार्य नहीं हैं। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है, हालांकि इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

ईरान जंग अभी भी बदस्तूर जारी है। 28 मार्च को इस जंग को एक महीना हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि ईरान इस युद्ध को खत्म करने चाहता है। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वह इस युद्ध को तभी समाप्त करेगा, जब उसकी शर्तें पूरी होंगी।

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की



समयसीमा तय करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से खारिज कर दिया है और अमेरिकी प्रस्ताव को एकतरफा बताया है।

ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के अनुसार, तेहरान ने युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा की है, लेकिन उसकी शर्तें उसे स्वीकार्य नहीं हैं। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है, हालांकि इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

ईरान की 5 शर्तें?

- ♦ दुश्मन की ओर से हमला और हत्याएं पूरी तरह रोकना।
- ♦ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना, जिसके तहत ईरान पर दोबारा युद्ध थोपा ना जा सके।
- ♦ युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे के भुगतान को स्पष्ट और गारंटीयुक्त व्यवस्था।
- ♦ पूरे क्षेत्र में शामिल सभी मोर्चों और सभी प्रतिरोधी समूहों के लिए युद्ध का पूर्ण समापन।
- ♦ होर्मुज पर अपने अधिकार के प्रयोग को लेकर ईरान के संप्रभु अधिकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता और गारंटी।

अपने गिरेबा में झांके पाकिस्तान: जायसवाल

नईदिल्ली। भारत ने एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े न्यायिक मामलों पर बयान को लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को झूठे और भ्रामक दावों के बजाय अपने यहां हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों पर विचार करना चाहिए।



मंत्रालय ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के इस बयान को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ऐसा देश इस तरह का बयान जारी कर निर्दोष लोगों की हत्या और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, जो लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठे और भ्रामक दावों के बजाय अपने यहां जारी गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय की ओर से यह सख्त प्रतिक्रिया तब आई है।

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स, तैराकी में छत्तीसगढ़ को 2 मेडल

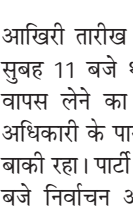
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत तैराकी स्पर्धाओं में बुधवार को 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (पुरुष और महिला वर्ग) का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। प्रतियोगिता के दौरान स्वमिंग पूल पर खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। छत्तीसगढ़ को तैराकी में 2 मेडल मिले हैं। 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में निखिल ने ब्रॉन्ज और



अनुष्का ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि कर्नाटक और ओडिशा को गोल्ड मेडल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड के अनुसार, फाइनल में अलग-अलग राज्यों के तैराकों ने भाग लिया, जिसमें कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, मेघालय और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन खास रहा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता 3 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें कुल 7 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक के मनीकांत एल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1:07.41 मिनट में रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ के निखिल जल्को ने 1.11.77 मिनट के समय के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।

नीतीश बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष

पटना। नीतीश कुमार को एक बार फिर निर्विरोध रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नामांकन के लिए सुबह 11 बजे तक का समय तय किया गया था, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। किसी दूसरे उम्मीदवार को सामने न आने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी की कमान सौंप दी गई है। जेडीयू की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आज, मंगलवार 24 मार्च, 2026 को सुबह 11 बजे थी। बयान में कहा गया कि नामांकन वापस लेने का समय खत्म होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी के पास सिर्फ नीतीश कुमार का नामांकन ही बाकी रहा। पार्टी ने ये भी बताया कि आज दोपहर 2.30 बजे निर्वाचन अधिकारी अनिल प्रसाद हेगड़े नीतीश कुमार के निर्वाचित होने का निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री बिहार सरकार, श्रवण कुमार और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।



8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे टिकटिंग सिस्टम और यात्रियों की सुविधा से जुड़े बड़े सुधारों की घोषणा की है। अब ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यह बदलाव पहले चार घंटे की सीमा से बढ़ाकर यात्रियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नया नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होगा। इसके साथ दूसरे रिफंड स्लेब में भी बदलाव किया गया है। अब 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर टिकट की कीमत से 50 प्रतिशत की कटौती होगी। इससे पहले यह सीमा 12 से 4 घंटे थी। ट्रेन छूटने से 72 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25 प्रतिशत कटौती होगी, जबकि 72 घंटे से अधिक पहले कैंसिलेशन पर, पूरी कीमत लौटाई जाएगी। इस दौरान रेलवे यात्रियों से केवल फ्लैट चार्ज ही लिया जाएगा। 72 घंटे से पहले अधिकतम रिफंड, केवल फ्लैट चार्ज कटेगा रेल मंत्री ने बताया कि नया रिफंड नियम ब्लैक मार्केटिंग और एजेंटों द्वारा आखिरी समय में टिकट बुकिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। जनवरी 2026 से शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ड्रूट ट्रेनों पर यह नियम पहले से ही लागू है। उन्होंने काउंटर टिकट खरीदारों के लिए क्लास अपग्रेड की सुविधा भी बढ़ाई।

सोनिया की बिगड़ी तबीयत, गंगाराम अस्पताल में भर्ती

नईदिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार देर शाम दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम फिलहाल इलाज में जुटी है। डॉक्टर अरूप बासु की देखरेख में उनका



इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि फेफड़ों से संबंधित परेशानी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, सोनिया गांधी की स्थिति अभी ठीक है। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड़ा भी अस्पताल पहुंचे थे। कुछ समय बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अस्पताल ने निकल दिया। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को इस साल जनवरी में भी सांस लेने में तकलीफ के कारण इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय डॉक्टरों ने बताया था कि दिल्ली की सर्दी और वायु प्रदूषण के चलते उनका ब्रोंकियाल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था। पिछले साल दिसंबर में सोनिया गांधी 79 साल की हो गईं। वह अभी राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हैं। उच्च सदन में आने से पहले वह पांच बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं।

अमेरिका के युद्ध विराम घोषणा से निकली शांति की किरण

मनोज कुमार अग्रवाल

अमेरिका का पांच दिन के लिए एक तरफा युद्ध विराम का एलान बेहद खराब दौर में पहुंच चुके हालात में शांति का संदेश वाहक बन रहा है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच ताजा घटनाक्रम इस ओर इशारा कर कर रहे हैं कि अब मिसाइल अटैक थमने को तैयार हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हालिया तनाव में आया यह अल्पविराम महज एक रणनीतिक उठराव नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए एक निर्णायक अवसर है। पिछले 24 दिनों से इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच जारी भयंकर युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पांच दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा करना निःसंदेह वैश्विक स्तर पर

एक राहत देने वाली खबर हैं। युद्ध जैसे विनाशकारी परिदृश्य में जब भी संवाद और विराम की संभावना बनती है, वह केवल संबंधित देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा की किरण लेकर आती है। ऐसे समय में जब हर दिन नई तबाही और अनिश्चितता का संदेश ला रहा था, अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। इसमें कोई दोमत नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत और सीमित समय के। के लिए सैन्य सैन्य कार्रवाई रोकने के संकेत ने वैश्विक स्तर पर उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। इसका कारण है कि यह केवल दो देशों के बीच

टकराव का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानवता पर पड़ रहा है। आजकल युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया को हिला देते हैं। तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ब पर सीधा प्रहार किया है। विकासशील देशों के लिए यह संकट और गहरा है, जहां महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ऐसे में यह युद्ध केवल तीन देशों का मसला नहीं, बल्कि पूरी मानवता के आर्थिक और सामाजिक संतुलन का प्रश्न बन चुका है। सामरिक दृष्टि से



देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को गहरी चोट पहुंचाई है। उसके पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया।

आपको पता रहे कि ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों और आधारभूत ढांचे को ध्वस्त कर ईरान को करीब 20 से 25 साल पीछे धकेल दिया

है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को अस्थायी रूप से टालने का निर्णय, भले ही पांच दिनों के लिए हो, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। यह दिखाता है कि युद्ध के बीच भी बातचीत की संभावना सरावाा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि, इस निर्णय को लेकर कई सवाल भी उठते हैं, खासकर तब जब ईरान ने किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत से इनकार किया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि स्थिति अभी भी अनिश्चितताओं से भिरी हुई है। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने काफी मजबूरी में युद्ध

विराम का फैसला लिया है। अमेरिका शुरुआती रणनीति में यह मानकर चला था कि सीमित सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के भीतर बाद ईरान के भीतर जन असंतोष उभरेगा और सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन यह आकलन गलत साबित हुआ। न तो जनता सड़कों पर उतरी और न ही सत्ता संरचना में कोई तत्काल बदलाव आया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बाहरी हस्तक्षेप के आधार पर किसी देश की आंतरिक राजनीति को बदलना इतना आसान नहीं है। युद्ध को आगे बढ़ाने का विकल्प अमेरिका के सामने था, लेकिन इसके साथ कई गंभीर जोखिम जुड़े थे। अफगानिस्तान और इराक के अनुभव पहले से ही अमेरिका के सामने हैं, जहां लंबे सैन्य अभियानों ने न

केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारी कीमत वसूल की। इस पूरे घटनाक्रम में खाड़ी देशों की भूमिका भी अहम रही है। ओमान, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों ने स्पष्ट संकेत दिए कि वे इस संघर्ष के विस्तार के पक्ष में नहीं हैं। उनके लिए यह युद्ध आर्थिक और सामरिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला होता, तो जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस संसाधन भी निशाने पर आ सकते थे। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ता। होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा भी इस संघर्ष के केंद्र में है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।

गृह मंत्री विजय शर्मा बोले: नक्सलवाद के समापन में इसरो ने भी किया सहयोग

जगदलपुर। बड़े नक्सली लीडर पापा राव के आत्मसमर्पण के साथ 31 मार्च तक नक्सलमुक्त बस्तर की घोषणा हकीकत में तब्दील हो रही है। इस सफलता के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई कारक हैं, इनमें से एक इसरो है, जिसका खुलासा गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज किया।

जगदलपुर में शौर्य भवन में मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलवाद के समापन में इसरो ने सहयोग किया है। जाहिर है इसमें इसरो द्वारा सेटलाइट के जरिए नक्सलियों की मूवमेंट की अहम भूमिका रही। नक्सलवाद के खामे के साथ बस्तर में बनाए गए सुरक्षाबलों के 400 कैंप को



लघु वनोपज केंद्र में तब्दील किया जाएगा।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में डीकेएसजेडसी स्तर का एक भी माओवादी नहीं बचा है। गिनती के माओवादी बचे हुए हैं, इनका भी पुनर्वास सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में तीन हवाय से अधिक

माओवादियों ने आत्म समर्पण किया है। दो साल में दो हजार माओवादियों को फोर्स ने गिरफ्तार किया है। सवा पांच सौ माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। फोर्स के जवानों के अद्भुत साहस से यह मुमकिन हुआ है। बस्तर संभाग के अलावा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले भी नक्सल मुक्त हुए हैं।

धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की घटना हिंदू संगठन का थाने में प्रदर्शन



■ **धमतरी के धार्मिक स्थल में छेड़छाड़ को लेकर हिंदू समाज आक्रोशित है, हिंदू संगठन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है**

धमतरी। धमतरी के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की घटना के बाद क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अज्ञात आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़

की।सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हिंदू जागरण मंच के संयोजक पुरुषोत्तम निषाद ने बताया कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं सहसंयोजक चित्रेश साहू ने बताया कि मंदिर में रोज पूजा करने आने वाले व्यक्ति ने इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने शहर में इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है।

धमतरी में डीजल जमाखोरी पर अब तक की बड़ी कार्रवाई पेट्रोल पंप संचालक के ठिकाने से 3100 लीटर डीजल जब्त

■ **जिले में पहली बार डीजल की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है.**

धमतरी। डीजल की जमाखोरी कर अवैध भंडारण का खुलासा हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा ही बड़े पैमाने पर डीजल जमा कर रखे जाने की जानकारी सामने आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई से जिले भर के जमाखोरों में हड़कंप मच गया है।

मंगलवार शाम थाना प्रभारी कुरुद को शिकायत के माध्यम से अवैध डीजल भंडारण की सूचना मिली। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद की निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए कुरुद-धमतरी रोड स्थित सर्वेश्वर ऑटो फ्यूल्स कुरुद पेट्रोल पंप में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पेट्रोल पंप के पीछे बने स्टोर रूम में भारी मात्रा

कुसमुंडा में पलाईओवर और फोरलेन सड़क के अधूरे निर्माण के खिलाफ आक्रोश

कोरबा। कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा में फोरलेन और पलाई ओवर निर्माण पिछले लगभग तीन से चार सालों से अधूरा है। इसके कारण रोज जाम की स्थिति निर्मित होती हैं। क्षेत्र के लोग खासे परेशान हैं। मंगलवार को लोगों का आक्रोश फूट, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों के साथ मिलकर लोगों ने चक्का जाम किया। प्रशासन के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद आंदोलन शाम को समाप्त हुआ।

इमलीछापर चौक में कांग्रेस द्वारा फोरलेन सड़क और ओवर ब्रिज निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था। स्थानीय लोग भी आंदोलन में शामिल रहे। इस चक्काजाम में जिला शहर व ग्रामीण कांग्रेस के



पदाधिकारी, बांकीमोंगरा व कुसमुंडा क्षेत्र के पदाधिकारी, पार्षद,व्यापारी व आमजनता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इमली छापर चौक में सुबह लगभग 11 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन दोपहर लगभग 4 बजे समाप्त हुआ। प्रशासन की ओर से दीपका तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी, निगम और एसईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिन्होंने लिखित में आश्वासन देते हुए अधूरे फोर

लेन निर्माण कार्य की 20 अप्रैल से शुरू करने के आश्वासन दिया। साथ ही ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का कोर्ट में मामला लंबित होना बताया।

इसके अलावा जाम से निजात के लिए कुसमुंडा प्रबंधन द्वारा 5 व्यक्ति प्रति शिफ्ट में तैनात करने की भी बात कही गई है। वहीं सर्वमंगला रोड से कुसमुंडा की ओर जाने वाले रोड में स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही गई है।

अफीम खेती मामले में निलंबन के विरोध में कृषि अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

■ **कृषि अधिकारी संघ का कहना है कि हड़ताल से जिले में कृषि विभाग की कई योजनाएं प्रभावित होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.**

दुर्ग। अफीम खेती मामले को लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के निलंबन के विरोध में कृषि अधिकारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के आह्वान पर विभाग के मैदानी अमले ने हिन्दी भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे अधिकारियों ने निलंबन को अनुचित बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंदोलनरत अधिकारी कामाक्षी त्रिवेदी ने बताया कि संघ द्वारा कलेक्टर और उपसंचालक से मुलाकात कर निलंबन निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया था। कलेक्टर ने विचार करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन 22 मार्च तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं

जग्गी हत्याकांड केस हाईकोर्ट में रिओपन

बिलासपुर। बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड केस हाईकोर्ट में रिओपन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सतीश जग्गी भी उपस्थित हुए। डिवीजन बेंच ने केस की अंतिम सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल, डिवीजन बेंच ने 2 साल पहले रामावतार जग्गी

हत्याकांड के दोषियों को अपील को खारिज कर दिया था। जिसमें डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया था, जिससे मामले की मेरिट पर विस्तार से सुनवाई हो सके। हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरूआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगने पर राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। तब सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए थे।



होने के कारण हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा।कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। संघ का कहना है कि इस हड़ताल से जिले में कृषि विभाग की कई योजनाएं प्रभावित होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग ने मादक फसलों से जुड़ी कोई स्पष्ट जानकारी या प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं करायी। ऐसे में बिना पर्याप्त दिशा-निर्देश के की गई कार्रवाई

पसंद की लड़की से शादी की ज़िद, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

अंबिकापुर। लुंड्रा थाना क्षेत्र में एक युवक का अजीबो-गरीब हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। पसंद की लड़की से शादी कराने की ज़िद पर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब 4 घंटे तक वहां बैठकर हंगामा करता रहा। युवक बार-बार युवती से शादी कराने की मांग कर रहा था। उसने चेतावनी दी कि यदि उसकी शादी नहीं कराई गई तो वह टावर से कूदकर जान दे देगा। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बताया जा रहा है कि जिस युवती को लेकर युवक टावर पर चढ़ा था, उसने पहले ही शादी से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, युवती ने युवक के खिलाफ बेवजह परेशान करने और छेड़छाड़ की शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत और समयझाझ के बाद युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया। खास बात यह रही कि यह पूरा ड्रामा लुंड्रा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर करीब 4 घंटे तक चलता रहा।

फरसगांव सहकारी बैंक में अत्यवस्था

■ **फरसगांव सहकारी बैंक में किसान परेशान हो रहे हैं.किसानों का आरोप है कि बैंक से उन्हें उतनी राशि नहीं मिल रही जितनी जरूरत है.**

कोंडगांव। फरसगांव स्थित जिला सहकारी बैंक में इन दिनों अव्यवस्था इस कदर बढ़ गई है कि किसानों को अपनी ही जमा राशि निकालने के लिए कई दिनों तक भटकना पड़ रहा है। बैंक की खराब व्यवस्था के कारण किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि वे सुबह से बैंक के बाहर धूप में



बैठकर इंतजार करते हैं, लेकिन बैंक अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी पूरी राशि नहीं मिलने से उन्हें बार-बार बैंक आना पड़ रहा है। किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि विड्रॉल फार्म भरने के दिन ही पूरी राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि खेती का काम समय पर हो सके वहीं बैंक प्रबंधन अपनी मजबूरी बता रहा है। बैंक के बाहर

किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं। कोई तीन दिन से तो कोई चार दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब नंबर आता है तो उन्हें केवल 10 से 20 हजार रुपये देकर वापस भेज दिया जाता है। इससे किसानों के सामने खेती-किसानी के काम प्रभावित होने का संकट गहरा गया है।खाद, बीज और मजदूरी के लिए समय पर पैसे नहीं मिलने से किसान परेशान हैं।

हाथी दांत तस्करी का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की एंटीपोंपिंग टीम को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। खेत में मिले जंगली हाथी के दांत को बेचने की फिराक में घूम रहे तीन आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक बेशकीमती हाथी दांत सहित भारी मात्रा में शिकार के आधुनिक और पारंपरिक उपकरण बरामद किए गए हैं।

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर शुरू हुई। सूचना मिली थी कि कुल्हाड़ीघाट निवासी पदमन के पास जंगली हाथी का दांत मौजूद है।

सहायक संचालक जगदीश प्रसाद दरों के निर्देशन में वनक्षेत्रपाल दिनेश चौधरी ने टीम गठित कर पदमन के घर और बाड़ी



की तलाशी ली। इस दौरान टीम दंग रह गई, जब पता चला कि आरोपी पदमन ने पिछले 4 वर्षों से हाथी के दांत को अपने घर की दीवार में चुनवाकर रखा है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पुसऊराम ग्राम सिहार निवासी का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। पुसऊराम इसी

साल दडईपानी क्षेत्र में हुए सांबर शिकार मामले में भी मुख्य आरोपी था और वर्तमान में जमानत पर बाहर था। जमानत पर रहते हुए फिर से वन्यजीव अपराध में सिलित पाए जाने पर विभाग ने इसे गंभीरता से लिया। वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास से कई सामग्रियां जब्त की है। इसमें 1

हाथी दांत ठोस स्थिति में, 2 धनुष, 12 तीर, चिड़िया मारने का विशेष धनुष, जंगली सुअर का दांत और बालों का एक गुच्छा, 2 गुलेल और घुर्रु शामिल है।

आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी सुखचंद ग्राम कठवा निवासी ने बताया कि उसने यह हाथी दांत साल 2021 में सिहार निवासी गंगाराम से लिया था। गौर करने वाली बात यह है कि गंगाराम की मौत सितंबर 2022 में हाथी-मानव द्वंद्व के दौरान हुई थी। आरोपियों का दावा है कि गंगाराम को यह दांत सिहार के एक खेत में पड़ा हुआ मिला था। हालांकि, वन विभाग इस दावे को संदिग्ध मान रहा है और दांत के सैंपल को डीएनए मैचिंग के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून भेजा जा रहा है ताकि हाथी की पहचान और मौत के कारणों का सुराग मिल सके।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से यूनीसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से बुधवार



को लोकभवन में यूनीसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता एवं एलियन इनोवेशन्स हैदराबाद के संस्थापक श्री रवि किरण ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विकसित नवीनतम सहायक उपकरण का प्रदर्शन किया और इसकी विशेषताओं की जानकारी दी। श्री रवि किरण ने बताया कि यह उपकरण दृष्टिबाधित लोगों को दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगा। भेंट के दौरान उन्होंने राज्य में दृष्टिबाधितजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी लॉन्च कार्यक्रम के लिए राज्यपाल को आमंत्रित भी किया। राज्यपाल ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर एलियन इनोवेशन्स की प्रमुख सुश्री हर्षिता भी उपस्थित थी।

निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित वाहनों के मालिक भुगतान हेतु 30 तक करें आवदेन

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन-2023, लोकसभा निर्वाचन-2024 एवं उप विधानसभा निर्वाचन-2024 के दौरान रायपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों तिल्पा, धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग एवं अभनपुर में निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित किए गए वाहनों के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक कई वाहन मालिक अपने वाहनों (स्कूल बस, विश्वविद्यालय बस एवं छोटे वाहन जैसे स्कॉर्पियो, इनोवा आदि) का भुगतान प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे सभी वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे 30 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 9 में उपस्थित होकर निर्वाचन पर्यवेक्षक से संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। भुगतान प्राप्त करने हेतु वाहन मालिकों को अपने साथ वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी. बुक), वाहन अधिग्रहण आदेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर तथा बैंक विवरण के लिए कैसल चेक लाना अनिवार्य है। निर्धारित समयवाधि में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित भुगतान राशि शासन को चालान के माध्यम से जमा कर दी जाएगी, भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय, रायपुर कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

पुणे के आचार्य रामनाथ की वाल्मिकी रामायण कथा 28 से

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में 28 मार्च से एक अप्रैल तक छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह (मिनी हाल) में वाल्मिकी रामायण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर आध्यात्मिक समिति की पदाधिकारियों की मंडल में शाम को हुई बैठक में जिम्मेदारी सौंपी गई। 28 मार्च को कथावाचक रामनाथ रामचंद्र अय्यर के आगमन से लेकर दो अप्रैल को हनुमान जयंती पर होने वाले नारदीय कीर्तन तक की रूपरेखा तैयार कर विभिन्न समितियां बनाई और इनके पदाधिकारी मनोनीत कर उन्हें काम सौंप गए। सचिव चेतन दंडवते ने बताया कि इस पांच दिवसीय आयोजन में बुवा पुणे से पधारे आचार्य रामनाथ श्रद्धालुओं और श्रोताओं को प्रभु श्रीराम के प्रेरक प्रसंगों पर प्रवचन देंगे।

कोडर परियोजना वितरक नहर के कार्यों के लिए 21.11 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग के अंतर्गत महासमुंद्र जिले की कोडर परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर के चिंगरौद वितरक नहर का सी.सी. लाईनिंग कार्य हेतु 21 करोड़ 11 लाख 92 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के उपरांत रूपांकित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 767 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति के साथ ही 210 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 3619 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होगी। योजना के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

अलायंस एयर 31 मार्च से शुरू कर रहा जगदलपुर-रायपुर फ्लाइट

रायपुर। बस्तर संभाग के लिए लंबे इंतजार के बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है। अलायंस एयर ने जगदलपुर-रायपुर सेक्टर पर दोबारा फ्लाइट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा 31 मार्च से समर शेड्यूल के तहत शुरू होगी, जिसमें हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर सेक्टर को शामिल किया गया है। काफी समय से इस रूट पर विमान सेवा बंद थी, जिससे यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि लगातार इस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। अब नई घोषणा के बाद बस्तर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

माता कौशल्या महोत्सव का मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने किया भव्य शुभारंभ

चंद्रखुरी धाम में श्रद्धा और संस्कृति की झलक, भगवान श्री राम हम सबके आराध्य, छत्तीसगढ़ सरकार उनके बताए हुए मार्ग पर चल रही है

रायपुर। ग्राम चंद्रखुरी (जिला रायपुर) स्थित पावन माता कौशल्या धाम में माता कौशल्या महोत्सव 2026 का भव्य और गरिमामय शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय इस महोत्सव के प्रथम दिवस पर श्रद्धा, भक्ति और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा। महोत्सव के पहले दिन दोपहर 3 बजे मानस मंडलियों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां तीन प्रमुख मंडलियों ने अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। सायं 6 बजे अतिथियों ने माता कौशल्या के दर्शन, पूजन एवं आरती कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की तथा इसके पश्चात विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए शासन की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं राजगीत के साथ प्रारंभ हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा अध्यक्षता सुश्री मोना सेन ने की। संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य ने स्वागत उद्घोहन देते हुए विभागीय गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, वहीं



अतिथियों ने अपने संबोधन में माता कौशल्या की महिमा, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत तथा लोक परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। रात्रि 8 बजे रंग छत्तीसा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमती पूनम विराट तिवारी एवं छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और देर रात तक तालियों की गुंज बनी रही।

चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या धाम देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यह स्थान भगवान श्रीराम की

छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को मिलेगी नई दिशा

■ **स्क्रिप्ट समिति गठन हेतु महत्वपूर्ण बैठक, कला-संस्कृति और सिनेमा के समन्वय पर जोर**

रायपुर। संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन की अध्यक्षता में स्क्रिप्ट समिति के गठन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रदेश में फिल्म निर्माण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को सिनेमा के माध्यम से व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखी जा रही है।

संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य ने सिनेमा और संस्कृति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों और क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने सहभागिता करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए।

बैठक में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. राजन यादव, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फोटो अधिकारी श्री अभिमन्यु सिन्हा, प्रसार भारती आकाशवाणी रायपुर से पंचश्री डॉ.



राधेश्याम तारक तथा प्रसार भारती दूरदर्शन रायपुर के कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.के. पाठक उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मुंबई से फिल्म अभिनेता श्री भगवान तिवारी ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए फिल्म निर्माण के व्यावहारिक पहलुओं और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में सदस्य सचिव के रूप में उप संचालक श्री उमेश मिश्रा ने समन्वय की भूमिका निभाई। बैठक के दौरान स्क्रिप्ट समिति के गठन की रूपरेखा, कार्यप्रणाली और चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। इस समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोककथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, जनजीवन और परंपराओं पर आधारित सशक्त और गुणवत्तापूर्ण पटकथाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय विषयवस्तु पर आधारित फिल्मों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने अपने विचार रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में

अपार रचनात्मक संभावनाएं हैं, जिन्हें दूरदर्शन रायपुर के कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.के. पाठक उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मुंबई से फिल्म अभिनेता श्री भगवान तिवारी ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए फिल्म निर्माण के व्यावहारिक पहलुओं और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में सदस्य सचिव के रूप में उप संचालक श्री उमेश मिश्रा ने समन्वय की भूमिका निभाई। बैठक के दौरान स्क्रिप्ट समिति के गठन की रूपरेखा, कार्यप्रणाली और चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। इस समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोककथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, जनजीवन और परंपराओं पर आधारित सशक्त और गुणवत्तापूर्ण पटकथाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय विषयवस्तु पर आधारित फिल्में को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

मंत्री अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात

■ **कहा- संवेदनशीलता, ईमानदारी और दक्षता से निभाए जनसेवा का दायित्व**

रायपुर। चंद्रखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने नव-निचुक युवा पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर प्रशिक्षण पूर्ण करने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि विश्वास, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक है, जिसे धारण करने वाले प्रत्येक अधिकारी पर समाज की सुरक्षा और न्याय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने उद्घोहन में कहा कि जब एक सामान्य नागरिक निश्चित होकर सोता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस निभाती है। जब अंधेरे में कोई भयभीत होता है, तो उसे उम्मीद भी पुलिस से ही होती है। ऐसे में पुलिस केवल एक संस्था नहीं, बल्कि समाज के विश्वास का आधार है।

उन्होंने आगे कहा कि आज 870 युवा प्रशिक्षु अधिकारी ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, जहां से वे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, शांति और न्याय व्यवस्था की मजबूत रीढ़ बनने जा रहे हैं। यह



केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे राज्य के विश्वास और अपेक्षाओं का प्रतीक है।

राज्य में बदलते सुरक्षा परिदृश्य का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने पिछले वर्षों में नक्सलवाद जैसी बड़ी चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। उन्होंने इसके लिए देश के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस व समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब चुनौतियां बदल चुकी हैं। साइबर अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती अफवाहें नई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को तकनीकी रूप से दक्ष और संवेदनशील बनना होगा।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इस बैच में

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे यह स्थल एक आदर्श धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है।

माता कौशल्या महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपरा और पहचान को सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण मंच भी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से जहां एक ओर श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूती मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। मुख्य अतिथि श्री गुरु खुशवंत साहेब ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

माता कौशल्या महोत्सव 2026 न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है, बल्कि राज्य सरकार की सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन विकास के प्रति प्रतिबद्धता का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिससे चंद्रखुरी धाम आज छत्तीसगढ़ की नई पहचान के रूप में स्थापित हो रहा है।

भारतीय रेल ने रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत पाँच नए सुधारों की घोषणा की

■ **माल ढुलाई, निर्माण और यात्रियों की सुविधा पर बल**

रायपुर/नई दिल्ली। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 2026 के दौरान सुधार करने के भारतीय रेल के संकल्प के अनुरूप, पाँच नए सुधारों को स्वीकृति दी गई है। इन नए सुधारों की मंजूरी के साथ, वर्ष 2026 के लिए सुधारों की कुल संख्या नौ हो गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत, चार सुधारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी और अब पाँच नए सुधार पेश किए जा रहे हैं। इन पाँच नए सुधारों में से दो माल ढुलाई से, एक निर्माण से और दो यात्रियों की सुविधा से संबंधित हैं।

पांचवां सुधार नमक के परिवहन पर केंद्रित है। इसके बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में नमक के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। नमक का उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्य तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान हैं। भारत में सालाना उत्पादित होने वाले लगभग 35 मिलियन टन नमक में से, लगभग 9.2 मिलियन टन प्रति वर्ष रेल द्वारा पहुंचाया जाता है, जो महत्वपूर्ण और ऐसा अवसर है जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नमक के परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी उसके उपयोग के अनुसार अलग-अलग होती है - औद्योगिक नमक के लिए यह लगभग 25 प्रतिशत है, और मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाले नमक के लिए यह लगभग 65 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे द्वारा



पहुँचाए जाने वाले कुल नमक का 62 प्रतिशत हिस्सा 1,000 से 2,500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे यह खंड रेल परिवहन के लिए बेहद उपयुक्त बन जाता है।

वैष्णव ने कहा कि नमक उत्पादकों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया ताकि इस क्षेत्र की चुनौतियों को समझा जा सके। इस अध्ययन में कई प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई, जिनमें वैगनों का अनुपयुक्त डिज़ाइन, नमक के कारण वैगनों में जंग लगना, तिरपाल से ढके होने के बावजूद खुले वैगनों में पानी का रिसाव होना, और सामान की कई बार लोडिंग-अनलोडिंग (हैंडलिंग) के कारण लागत में वृद्धि और नुकसान होना शामिल हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए अब स्टेनलेस स्टील से बना, ऊपर से लोड होने वाला और बगल से खाली होने वाला कंटेनर सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह कंटेनर जंग से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, और इसमें ऊपर से लोड करने के लिए फ्लैप तथा बगल से खाली करने के लिए हाइड्रोलिक तंत्र लगा है, जिससे गंतव्य स्थान पर ट्रकों में नमक को आसानी से अनलोड किया जा सकता है।

लगाभ एक चौथाई बेटियों की भागीदारी

प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने महिला अधिकारियों को समाज में सुरक्षा और सशक्तिकरण की नई पहचान बताया। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की कि वे जनता के साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार करें तथा अपने कार्य में ईमानदारी और निष्पक्षता को सर्वोपरि रखें।

उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी वही होता है, जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है और संकट की घड़ी में सबसे आगे खड़ा रहता है। साथ ही, जहां भी उनकी नियुक्ति हो, वहां को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए जनता के साथ विश्वास का रिश्ता बनाना चाहिए।

अपने संबोधन के अंत में मंत्री श्री

अग्रवाल ने कहा कि डर पैदा मत कीजिए, विश्वास पैदा कीजिए। शक्ति का प्रदर्शन मत कीजिए, न्याय का संरक्षण कीजिए। वर्दी केवल तन पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र और आत्मा में धारण कीजिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस दिन कोई नागरिक यह कहे कि पुलिस है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, उसी दिन एक पुलिस अधिकारी की वर्दी सार्थक होगी।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला

बलरामपुर-रामानुजगंज, मुख्यालय बलरामपुर (छग)

फोन नम्बर 07831-299063 ई-मेल - acbalrampur@gmail.com

-: निविदा तिथि में संशोधन सूचना पत्र:-

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 3663 / निर्माण आ.वि./2026 बलरामपुर, दिनांक 27.02.2026 के तहत निविदा क्रमांक 183036 कार्य का नाम:- प्रयास आवसीय विद्यालय जिला बलरामपुर भवन निर्माण लागत राशि 24,06,00,000-00 (रूपये चौबीस करोड़ छः लाख मात्र) जारी किया गया है। जिसका रिफरेंस नंबर 252603008387 तथा एडवरटाईज नंबर जी-252607032/7 है।

उपरोक्त निविदा में कई बार Corrigenandum किये जाने के कारण निविदा की तिथियों में आंशिक संशोधन किया जाता है।

संशोधित ई-टेंडरिंग की निर्धारित तिथि का विवरण इस प्रकार है:-

1. ई-निविदा जमा करने की तिथि:- दिनांक- 06.04.2026 समय सांय 5.30 बजे तक

2. निविदा लिफाफा जमा करने :- दिनांक-13.04.2026 समय सायं. 5.30 बजे तक की अंतिम तिथि

3. प्रोजेक्ट प्रजेन्टेशन की तिथि :- दिनांक- 16.04.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

4. निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक- 21.04.2026 दोपहर 12.00 बजे से

(जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित)

उक्त संशोधित तिथि को अपलोड कर दिया गया है जिसे वेबसाइट https://eproc. cgstate.gov.in/ में देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास

बलरामपुर-रामानुजगंज

जी-252607385/9

बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन?

सनत जैन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा भाजपा के ऊपर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा,अघोषित रूप से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा गया है। एसआईआर के माध्यम से 63 लाख लाख मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा रहा है। मतदाता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची मे नहीं थे। उन मामलों की सुनवाई अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश चुन्मेदवार आयोग को दिए थे। चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जा रहे हैं।यह स्थिति आपातकाल की तरह है। चुनाव आयोग राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बिना एक तरफा निर्णय ले रहा है। ममता बनर्जी ने तीखा हमला करते हुए कहा, अब जो भी अच्छा बुरा पश्चिम बंगाल में होगा। उसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। जिस तरह से अधिकारियों को हटया गया है। उसके कारण पश्चिम बंगाल की सारी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद सारे निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था से लेकर हर स्थिति के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक हुई हैं। उससे लगता है,उन्होंने दिल्ली में जो कुछ केजरीवाल सरकार के साथ हुआ था। उसको ध्यान में रखकर सबक लिया है। केजरीवाल सरकार भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थीउप राज्यपाल और चुनाव आयोग के माध्यम से सारे निर्णय लिए जा रहे थे। सारा ठीकका केजरीवाल के सिर पर फोड़ा गया। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था। इसी तरह से केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाकर, वोट काटकर चुनाव आयोग द्वारा पक्षपात कार्यवाही करके सुंयोजित तरीके से आम आदमी पार्टी को हरया गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी अपनी बलि नहीं देना चाहती हैं। ऐसा लगता है ममता दीदी काली माई के रोद्र रूप को धारण करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से लड़ने के लिए चुनाव मैदान में अस्त्र-शस्त्र के साथ आ गई हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया कह दिया है। इससे उनके आक्रामक तेवर का पता लगता है। ममता बनर्जी पिछले 6 महीनो से एसआईआर की लड़ाई जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। मतदाता सूची फाइनल हुए बिना चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी तरह से चुनाव भी करा दिए जाएंगे। बिहार में भी ऐसा ही किया गया था। मनमाने तरीके से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को भाजपा के इशारे पर बदला जा रहा है। चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा धमकाया जा रहा है। इस तरह का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सड़क पर आकर लड़ाई लड़कर चुनाव मैदान में उतर रही हैं।जनता हमेशा आक्रामक तेवर के नेताओं को स्वीकार करती है। यह बात ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से भाजपा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उसके बाद केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के लिए ममता का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। चुनाव में धांधली और मनमानी कर पाना आसान नहीं होगा। इस चुनाव में सत्ता तक पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार दिख रही हैं।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...) वैदिक-स्वरूप (क) इन्द्रो मायाभिः पुरुषप् ईयते। (ख) अहल्याया ह, मैत्रेय्याः (इन्द्रः) जार आस। (ग) अहल्यायै जारेति। (च) सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्तात्। (ङ) अहल्यायै जारेति। (च) अहल्यायै जारेति। (छ) (इन्द्र !) अहल्यायै जारेति। अर्थात्- (क) इन्द्र माया से अनेक रूप बनाकर	(ख) इन्द्र मैत्रेयी अहल्या का जार था। (ग) अहल्या का जार। (घ) गौतम के शापानुग्रह करने पर पूर्व दिशा का स्वाभी इन्द्र सहस्राक्ष हो जाने के कारण अतिपश्य क्रान्तदर्शी हुआ (ङ, च, छ) इन्द्र अहल्या का जार। पौराणिक स्वरूप (क) सहस्रभगसम्प्राप्तिदुःखं चैव शचोपते । स्वर्गाद् भ्रशस्तथावासः कमले मानसे सरं ।। (देवीभागवत १ । 5।4६) (ख) एकदा गोतमः शोभ्र जगाम शंकरालयम्। शक्रो गोतमरूपेण तां तु भोगं चकार सः।। नगनामहल्यां रहसि पीनश्रेष्ठप्रयोधराम्। मुनिः शशाप शक्रं वै भगादृस्त्वं भवेति च।। कोपाच्छाशप पर्बी च सुदती भयविह्वलाम्। त्वं वे पाषाणरूपा च महारप्ये भवेति च।। (ब्रह्मवैवर्त क० ज० खण्ड 61 । 44--४6) क्रमशः ...
--	---



लिटिल इंडिया पर मिसाइल दाग ईरान ने दिया मैसेज या कर दी भूल

अभिनय आकाश	
 किसी भी चरण का युद्ध बेहद गंभीर मामला होता है। खासकर जब इसमें इज़राइल और अमेरिका शामिल हों। लेकिन ईरान पर थोपा गया यह युद्ध पिछले 48 घंटों में अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही है। पिछले 48 घंटों में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिनसे पता चलता है कि यह युद्ध पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। इसके वैश्विक परिणाम भी अब स्पष्ट हो गए हैं। पहली बात, इस युद्ध में अब परमाणु शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। खुद को विजैता घोषित करने के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और अल्टीमेटम दिया है और यह अल्टीमेटम बेहद हताशा भरा है। अगर ईरान इस अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 24-48 घंटों में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी इलाके में मौजूद डिमोना और अराद में मिसाइल अटैक किया है। 100 लोगों के घायल होने की खबर है। डिमोना वो जगह है जहां से 13 किमी की दूरी पर नेगेव रेगिस्तान है। नेगेव रेगिस्तान जहां पर इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस लोकेशन के इर्दने करीब मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाना इजराइल की बड़ी चुक मानी जा रही है। सबसे पहले, परमाणु मुद्दे पर बात करते हैं। इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। अगर आप मीडिया पर गौर करें तो आपको लगेगा कि ईरान ने इज़राइल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह हमला जानबूझकर न किया गया हो। डिमोना के पास स्थित शिमोन पेरेस परमाणु अनुसंधान संयंत्र पर हमला नहीं हुआ है। बल्कि डिमोना शहर पर हमला हुआ है, जहां उस संयंत्र में काम करने वाले लोग रहते होंगे। यह हमला जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया है... ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने नतान्ज् पर फिर से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इज़राइल के परमाणु संयंत्र के पास स्थित डिमोना शहर पर	



हमला कर दिया। और यह हमला एक संदेश देने के उद्देश्य से क्यों किया गया? अराद पर भी हमला किया गया है, लेकिन डिमोना पर हुआ यह हमला इतना खास क्यों है? मिसाइल इंटरसेप्ट में हुई चूक पर इजराइल क्या बोला और डेमोना का भारत से क्या तात्लुक है? इसे लिटिल इंडिया क्यों कहते हैं? आज इसी का एमआरआई स्कैन करेंगे। अगर किसी परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं होता, तो यह इतना खास क्यों है? जरा सोचिए, अगर कोई देश आकर हमारे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास हमला कर दे, तो हमारे देश को क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरह ही डिमोना में भी उनका एक परमाणु संयंत्र है। इसी अनुसंधान केंद्र ने इज़राइल को पहले 13 परमाणु हथियार मुहैया कराए थे। वहीं से यूरेनियम का उत्पादन हुआ था और वहीं से, मुझे लगता है 1967 में, इज़राइल को परमाणु हथियार मिले थे। आज जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसी संयंत्र के पास एक बम गिराया गया। ईरान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कि अगर हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला होता है, तो आपके परमाणु संयंत्र भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं।

अराद शहर में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद तबाही का भारी मजर देखने को मिला। रियायशी इमारतों के बीच हुए इस धमाके में कई लोग घायल हो गए। जेरुसलम पोस्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति ने बताया, अलर्ट के बाद हम शेल्टर में गए थे। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ, पूरा घर हिल गया। बाहर निकलने पर घर के खिड़की दरवाजे उखड़े नजर

अभय पांडेय

महादेवी वर्मा केवल एक नाम नहीं, हिंदी साहित्य की वह रोशनी थीं, जिसने अपनी कविताओं से असंख्य दिलों को छुआ। जिन्हें प्यार से आधुनिक मीरा भी कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिकता की वही गहराई झलकती है, जो मीरा की भक्ति में थी।

26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मीं महादेवी का बचपन साहित्य और संस्कारों की छांव में बीता। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा के थे, तो मां हेमरानी देवी धार्मिक थीं और संस्कृत व हिंदी की विदुषी भी। यही कारण था कि महादेवी के मन में बचपन से ही शब्दों की महक बस गई थी। इंदौर के मिशन स्कूल से पढ़ाई की

शुरुआत हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला सीखी, लेकिन उनके दिल को जो सबसे ज्यादा भाया, वह था साहित्य का संसार। मां ने उनकी इस रुचि को हमेशा प्रोत्साहित किया और यही सहारा आगे चलकर उन्हें साहित्य की बुलंदियों तक ले गया।

महादेवी वर्मा छायावादी युग की उन स्तंभों में से थीं, जिन्होंने हिंदी कविता को एक नई आत्मा दी। उनके शब्द केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि वेदना, प्रेम और विरह का स्पंदन थे। उनकी कविता में नीर भरी दुख की बदली में गहराई से महसूस किया जा सकता है कि कैसे वेदना में भी एक अनकही शक्ति होती है—

मैं नीर भरी दुख की बदली!



स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा,
क्रन्दन में आहत विश्व हंसा!
वे प्रेम से अधिक विरह को महत्वपूर्ण मानती थीं, क्योंकि यही भाव मनुष्य को भीतर से मौजता है। उनकी कविता मिलन का मत नाम

लो में उनकी यह भावना स्पष्ट झलकती है—

मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं!

महादेवी वर्मा की रचनाएं केवल प्रेम और पीड़ा तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिकता और स्त्री स्वाधीनता को भी अपने लेखन में उतारा।

ईश्वर की खोज उनकी कई कविताओं में झलकती है, जिनमें से कौन तुम मेरे हृदय में खास है।

साथ ही, उन्होंने अपने समय की महिलाओं की स्थिति पर भी गंभीरता से

लिखा। उनकी कालजयी कृति शृंखला की कड़ियां महिलाओं की स्वतंत्रता और समाज में उनके संघर्षों का दस्तावेज है। उनकी कविता कीर का प्रिय, आज पिंजर खोल दो स्त्री के बंधनों को तोड़ने की बात करती है।

महादेवी वर्मा ने केवल कविताओं तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने गद्य में भी अपनी कलम से संवेदनाओं की नई इबारतें लिखीं। उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, शृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, और मेरा परिवार हैं। महादेवी वर्मा महात्मा बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित थीं। वह मानती थीं कि जीवन दुख का मूल है, और यही भावना उनकी कविताओं में बार-बार दिखाई देती है। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने घर-गृहस्थ छोड़ संन्यासी बनने का मन बना लिया था।

समाचार पचीसा	
रायपुर, गुरुवार 26 मार्च 2026	
बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन?	
सनत जैन	
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा भाजपा के ऊपर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा,अघोषित रूप से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा गया है। एसआईआर के माध्यम से 63 लाख लाख मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा रहा है। मतदाता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची मे नहीं थे। उन मामलों की सुनवाई अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश चुन्मेदवार आयोग को दिए थे। चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जा रहे हैं।यह स्थिति आपातकाल की तरह है। चुनाव आयोग राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बिना एक तरफा निर्णय ले रहा है। ममता बनर्जी ने तीखा हमला करते हुए कहा, अब जो भी अच्छा बुरा पश्चिम बंगाल में होगा। उसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। जिस तरह से अधिकारियों को हटया गया है। उसके कारण पश्चिम बंगाल की सारी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद सारे निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था से लेकर हर स्थिति के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक हुई हैं। उससे लगता है,उन्होंने दिल्ली में जो कुछ केजरीवाल सरकार के साथ हुआ था। उसको ध्यान में रखकर सबक लिया है। केजरीवाल सरकार भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थीउप राज्यपाल और चुनाव आयोग के माध्यम से सारे निर्णय लिए जा रहे थे। सारा ठीकका केजरीवाल के सिर पर फोड़ा गया। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था। इसी तरह से केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाकर, वोट काटकर चुनाव आयोग द्वारा पक्षपात कार्यवाही करके सुंयोजित तरीके से आम आदमी पार्टी को हरया गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी अपनी बलि नहीं देना चाहती हैं। ऐसा लगता है ममता दीदी काली माई के रोद्र रूप को धारण करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से लड़ने के लिए चुनाव मैदान में अस्त्र-शस्त्र के साथ आ गई हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया कह दिया है। इससे उनके आक्रामक तेवर का पता लगता है। ममता बनर्जी पिछले 6 महीनो से एसआईआर की लड़ाई जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। मतदाता सूची फाइनल हुए बिना चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी तरह से चुनाव भी करा दिए जाएंगे। बिहार में भी ऐसा ही किया गया था। मनमाने तरीके से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को भाजपा के इशारे पर बदला जा रहा है। चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा धमकाया जा रहा है। इस तरह का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सड़क पर आकर लड़ाई लड़कर चुनाव मैदान में उतर रही हैं।जनता हमेशा आक्रामक तेवर के नेताओं को स्वीकार करती है। यह बात ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से भाजपा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उसके बाद केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के लिए ममता का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। चुनाव में धांधली और मनमानी कर पाना आसान नहीं होगा। इस चुनाव में सत्ता तक पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार दिख रही हैं।	

ज्ञान/मीमांसा	
हुमायु-ओवेसी के गठबंधन से क्या टीएमसी कमजोर होगी	
सौरभ वार्षण्य	
पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनने की आहट अक्सर सियासी बहस को तेज कर देती है। हाल के दिनों में हुमायु कबीर और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेादुल मुस्लिमीन के संभावित गठबंधन की चर्चा इसी संदर्भ में देखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे तृणमूल कांग्रेस कमजोर होगी? जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की पकड़ बहुत मजबूत है। गांव-गांव ममता की की छवि प्रभावशील नेता के रूप में विख्यात है। ममता दीदी के नाम से सब जगह उन्हें प्यार दुलार के रूप में देखा जाता है। ममता को कम आंकना बेइमानी होगी। वहीं भाजपा को अन्य राज्यों में हुए चुनाव में समीकरण देखने से पता चता है कि आवेसी की पार्टी ने कुछ हद तक प्रभाव डाला है। अब ऐसे में ममता की तीसरी पारी कैसी होगी यह समय के गर्त में है।	
पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे समय हो रहा है जहां विश्व में कई देश में युद्ध की आग में झुके हुए हैं। जिससे पूरे विश्व में चीजें अवरुद्ध हो रही हैं। ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो निश्चित ही महंगाई भी चरम सीमा पर होगी। अगर देखा जाये तो वोट बैंक की राजनीति और प्रभावित होगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अब तक बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेादुल मुस्लिमीन की रणनीति आमतौर पर इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की रही है, जैसा कि उसने बिहार और अन्य राज्यों में करने की कोशिश की। यदि हुमायु कबीर जैसे स्थानीय प्रभाव वाले नेता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेादुल मुस्लिमीन के साथ आते हैं, तो कुछ इलाकों में वोटों का बंटवारा संभव है। हालांकि, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि इससे टीएमसी को बड़ा नुकसान होगा। इसके पीछे कुछ कारण हैं संगठनात्मक मजबूती ममता बनर्जी के नेतृत्व में जमीनी नेटवर्क की मजबूत है। स्थानीय बनाम बाहरी छवि बंगाल की राजनीति में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा अहम रहता है, और ओवेसी की पार्टी को अक्सर बाहरी पार्टी के रूप में देखा जाता है।	
वोट ट्रांसफर की चुनौती: गठबंधन बनने के बावजूद वोटों का पूरी तरह ट्रांसफर होना आसान नहीं होता। किन क्षेत्रों में असर संभव? सीमावर्ती	

हुमायु-ओवेसी के गठबंधन से क्या टीएमसी कमजोर होगी	
सौरभ वार्षण्य	
पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनने की आहट अक्सर सियासी बहस को तेज कर देती है। हाल के दिनों में हुमायु कबीर और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेादुल मुस्लिमीन के संभावित गठबंधन की चर्चा इसी संदर्भ में देखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे तृणमूल कांग्रेस कमजोर होगी? जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की पकड़ बहुत मजबूत है। गांव-गांव ममता की की छवि प्रभावशील नेता के रूप में विख्यात है। ममता दीदी के नाम से सब जगह उन्हें प्यार दुलार के रूप में देखा जाता है। ममता को कम आंकना बेइमानी होगी। वहीं भाजपा को अन्य राज्यों में हुए चुनाव में समीकरण देखने से पता चता है कि आवेसी की पार्टी ने कुछ हद तक प्रभाव डाला है। अब ऐसे में ममता की तीसरी पारी कैसी होगी यह समय के गर्त में है।	
पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे समय हो रहा है जहां विश्व में कई देश में युद्ध की आग में झुके हुए हैं। जिससे पूरे विश्व में चीजें अवरुद्ध हो रही हैं। ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो निश्चित ही महंगाई भी चरम सीमा पर होगी। अगर देखा जाये तो वोट बैंक की राजनीति और प्रभावित होगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अब तक बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेादुल मुस्लिमीन की रणनीति आमतौर पर इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की रही है, जैसा कि उसने बिहार और अन्य राज्यों में करने की कोशिश की। यदि हुमायु कबीर जैसे स्थानीय प्रभाव वाले नेता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेादुल मुस्लिमीन के साथ आते हैं, तो कुछ इलाकों में वोटों का बंटवारा संभव है। हालांकि, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि इससे टीएमसी को बड़ा नुकसान होगा। इसके पीछे कुछ कारण हैं संगठनात्मक मजबूती ममता बनर्जी के नेतृत्व में जमीनी नेटवर्क की मजबूत है। स्थानीय बनाम बाहरी छवि बंगाल की राजनीति में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा अहम रहता है, और ओवेसी की पार्टी को अक्सर बाहरी पार्टी के रूप में देखा जाता है।	
वोट ट्रांसफर की चुनौती: गठबंधन बनने के बावजूद वोटों का पूरी तरह ट्रांसफर होना आसान नहीं होता। किन क्षेत्रों में असर संभव? सीमावर्ती	



जिलों और मुस्लिम बहुल सीटों—जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर—में इसका कुछ असर दिख सकता है। लेकिन यह असर अधिकतर टीएमसी को हारने की बजाय विपक्षी वोटों के और बिखराव के रूप में सामने आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के गठबंधन का अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यदि विपक्षी वोट बंटते हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को बढ़त मिल सकती है।

हुमायु कबीर गठबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर चुनौती जरूर खड़ी कर सकता है, लेकिन इसे टीएमसी की व्यापक कमजोरी के रूप में देखना अभी उचित नहीं होगा। यह ज्यादा संभावना है कि इससे विपक्षी खेमे में वोटों का विभाजन बदे, जिसका लाभ किसी तीसरे पक्ष को मिल सकता है। कुल मिलाकर, यह गठबंधन बंगाल की राजनीति में हलचल तो पैदा करेगा, लेकिन टीएमसी की जड़ों को हिलाने के लिए अभी और मजबूत, व्यापक और संगठित चुनौती की जरूरत है।

भारतीय राजनीति में ममता का नाम एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने जमीनी संघर्ष से सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। उनका राजनीतिक जीवन केवल पद और सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि जिद, जनसंपर्क और निरंतर संघर्ष की दास्तान है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ। साधारण परिवार से आने वाली ममता ने कम उम्र में ही राजनीति में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने छात्र जीवन से ही सक्रिय राजनीति में भाग लिया और जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गईं। 1970-80 के दशक में उन्होंने कांग्रेस के युवा चेहरों में अपनी पहचान बनाई। 1984 में

साबित हुआ। टीएमसी ने धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की और वाम मोर्चे के लंबे शासन को चुनौती दी। 34 वर्षों से सत्ता में रही सरकार को 2011 में ममता बनर्जी ने सत्ता से बेदखल कर दिया। यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन था। ममता बनर्जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और उन्होंने खुद को दीदी के रूप में जनात के बीच स्थापित किया। ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी और जनसंवाद है। वे अक्सर सीधे जनता के बीच जाती हैं और खुद को एक आम नागरिक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी सरकार ने कई सामाजिक योजनाएं शुरू कीं, जैसे— कन्याश्री योजना (महिला सशक्तिकरण), सबुज साथी (छात्रों के लिए साइकिल), स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, विवाद और चुनौतियां आदि।

हर बड़े नेता की तरह ममता बनर्जी का सफर भी विवादों से अछूता नहीं रहा। विपक्ष अक्सर उन पर तृष्णिकरण की राजनीति का आरोप लगाता है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव भी उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। चुनावी हिंसा और प्रशासनिक फैसलों पर भी सवाल उठते रहे हैं।

ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन यह साबित करता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और जनसमर्थन से असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा दी और खुद को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। आज वे केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति की एक मजबूत आवाज भी हैं—जो सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस रखती हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है।

महादेवी वर्मा जयंती

स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा,

क्रन्दन में आहत विश्व हंसा!

वे प्रेम से अधिक विरह को महत्वपूर्ण मानती थीं, क्योंकि यही भाव मनुष्य को भीतर से मौजता है। उनकी कविता मिलन का मत नाम

लो में उनकी यह भावना स्पष्ट झलकती है—

मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं!

महादेवी वर्मा की रचनाएं केवल प्रेम और पीड़ा तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिकता और स्त्री स्वाधीनता को भी अपने लेखन में उतारा।

ईश्वर की खोज उनकी कई कविताओं में झलकती है, जिनमें से कौन तुम मेरे हृदय में खास है।

साथ ही, उन्होंने अपने समय की महिलाओं की स्थिति पर भी गंभीरता से

आज का इतिहास

1917	प्रथम विश्व युद्ध- फिलिस्तीन में आगे बढ़ने का प्रयास, गाजा के प्रथम युद्ध में ओटोमन सैनिकों द्वारा अंग्रेजों को हरया गया था।
1943	एल्सी एस ओट्टू को अमेरिकी वायुसेना पदक मिला और वह यह पदक पाने वाली पहली महिला बनीं।
1953	जोनास सॉल्क ने अपने पोलियो वैक्सिन के वयस्कों और बच्चों के एक छोटे समूह को सफल परीक्षण की घोषणा की।
1971	शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को बंगलादेश के रूप में स्वतंत्र देश घोषित किया। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
1973	द यंग एंड द रेस्टलेस का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था, जो अंततः 1988 से अमेरिकालेविजन पर सबसे अधिक देखा जाने वाला दिन का नाटक बन गया।
1973	लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं की भूटी की थी।
1978	जपान के नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्धारित उद्घाटन से चार दिन पहले, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मोलोटोव कॉकटेल के साथ नियंत्रण टॉवर में बहुत सारे उपकरण नष्ट कर दिए।
1979	30 साल से जारी युद्ध विराम के लिए इसराइल और मिस्र ने शांति समझौते पर हाथ मिलाए। यह समझौता अमेरिका द्वारा करवाया गया था।
1983	अमेरिका ने नवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1992	हैवीवेत बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन को बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी।
1997	कैलिफोर्निया के रैंचो सांता फ़े में पुलिस ने हेवेन गेट के 39 सदस्यों के शवों की खोज की जिनकी एक स्पष्ट पंथ आत्महत्या में मृत्यु हो गई थी।
1999	जैक-केवोरियन, एक अमेरिकी वकील और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या के व्यवसायी के लिए, एक बीमार रोगी की मौत में हत्या का दोषी पाया गया था।
2000	व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने गए।
2000	मिचल क्रिस्टल ने 72 वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर समारोह की मेजबानी की। अमेरिकन ब्यूटी ने सर्वश्रेष्ठ चित्र जीता, केविन स्पेसी और हिलेरी स्वंक ने मुख्य अभिनय पुरस्कार जीते।
2006	18 वा राष्ट्रमंडल खेल मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में बंद किया गया।
2006	स्कॉटलैंड के बार और रेस्तरां में धूम्रपान पर प्रतिबंध है।
2011	टोख्यो की रिपोर्ट है कि इसकी जल आपूर्ति में विकिरण का स्तर सामान्य पर लौट आया है।

क्या पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सर्वाणों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे?

कमलेश पांडे

देश के पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके मतदान/परिणाम भाजपा नीत एनडीए को भावी रीति-नीति और सर्वाणों के सामाजिक-राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। बताया जाता है कि यदि इन चुनावों को भाजपा नीत गठबंधन जीत जाता है तो वह ओबीसी-दलित वोटरों को रखाने के लिए सर्वाण विरोधी एजेंडों को इत्मीनान पूर्वक धार देगा!

ऐसा इसलिए कि सामान्य जातियों से जुड़े सर्वाण वोटर ही भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए भी जिस तरह से सर्वाण विरोधी यूजीसी इक्विटी बिल लाया गया है, उससे सामान्य जातियों के लोग अर्थात सर्वाण समुदाय का एक बड़ा तबका अपनी मुख्य पार्टी भाजपा से काफी नाराज हैं और बदलती राजनीति के बीच वे किधर करवट लेंगे, यह बात पूरी तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।

राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए भाजपा कांग्रेसी राज और समाजवादी भाज के दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक व भाषाई क्षेत्र सम्बन्धी नीतियों को और अधिक धार दे रही है। आरक्षण, जातीय जनगणना, एससी-एसटी एक्ट से जुड़े परोक्षित प्रावधान, कमाऊ मंदिर संचालन जैसी नीतियों में पहले की सरकारों में और अब की सरकार में कोई अंतर नहीं आया है।

कोढ़ में खाज यह कि भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे से भटकती प्रतीत हो रही है। ऐसे में सत्ता के जातीय, सांप्रदायिक और भाषाई-क्षेत्रवाद की मानसिकता में कोई बदलाव न देख देश का सामाजिक इंजन वगं यानी सर्वाण समुदाय भाजपा से काफी नाराज है और यूजीसी इक्विटी बिल ने आग में घी का काम किया है।

चूँकि सर्वाण वोट कभी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय

दलों का भी कोर वोट बैंक हुआ करता था, और इनकी दलित-ओबीसी आरक्षण व अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियों से आजिज होकर भाजपा के आकर्षक मंडल विरोधी कमण्डलवाद पर फिदा हो चुका था, वह मोदी-शाह युग में एक के बाद दूसरे झटके लगाते रहने से सियासी विकल्प ढूँढ रहा है। चूँकि भाजपा नेतृत्व पूंजीपतियों के इशारे पर ब्राह्मण-राजपूत नेतृत्व को दरकिनार करते हुए ओबीसी-दलित नेतृत्व को मजबूत कर रहा है, इससे भी सर्वाण वर्ग में नाराजगी है।

यही वजह है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा के खिलाफ पनपे सर्वाण प्रतिरोध को पूरी तरह से अंदर ही अंदर धुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका दलित-ओबीसी-अल्पसंख्यक कोर वोट बैंक नाराज भी न हो और सर्वाण भी उनकी ओर लौट जाएं, ताकि अबतक की हारी हुई बाजी को पुनः जीता जा सके और यत्र तत्र जीती हुई बाजी को बरकरार रखाक जा सके! हालांकि, अब वे अपनी कोशिशों में कितने कामयाब होंगे, यह तो मतदान/मतगणना बाद ही पता चल पाएगा।

वहीं, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश के पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम सर्वाणों के सामाजिक-राजनीतिक भविष्य को तय नहीं करेंगे, भले ही भाजपा इन चुनावों में पश्चिम बंगाल और असम जीत जाए और तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में पहले से ज्यादा मजबूत होकर जीते। क्योंकि यूजीसी इक्विटी बिल के अंतर्गत सर्वाण जनक्रांश को डैमेज-कंट्रोल करने के लिए भाजपा-आरएसएस के रणनीतिकार जुट गए हैं, हालांकि उन्हें भी यह आशंका है कि ये चुनाव भाजपा के सर्वाण वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी हैं! वहीं, भाजपा की ओर कितने दलित-ओबीसी वोटर लौटते हैं, इससे भाजपा को सियासी तंदुरुस्ती मिलेगी।



भाजपा की सर्वाण लांबी का कहना है कि अब भी सर्वाण वोट पार्टी के कोर सपोर्टर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास भाजपा से उम्दा विकल्प मौजूद नहीं है। जबकि भाजपा अपनी चुनावी जीत के लिए दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटों पर ही निर्भर करती है। इसलिए वह सभी समुदायों के बीच राष्ट्रवादी तालमेल बिटाने में जुटी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देश, भारत के खिलाफ नहीं खड़े हों, इसलिए भाजपा ने भी कुछ बदलावों के साथ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीतियों को अपना लिया है।

मसलन, यदि 5 राज्यों में हो रहे चुनावों की चुनावी पृष्ठभूमि पर नजर डाली जाए तो 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए मतदान 23–29 अप्रैल 2026 को होंगे। वहीं असम की 126 विधानसभा सीटों, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों, केरल की 140 विधानसभा सीटों और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। इन चुनावों में भाजपा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम पर फोकस कर रही है। क्योंकि जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 सीटें मिलीं थीं। वहीं, असम में भाजपा की सत्ता बरकरार रहा गई थी और अभी वहां भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है।

इसलिए, जहां तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सर्वाणों की भूमिका की बात है तो भाजपा को सर्वाण यानी ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य आदि से मजबूत समर्थन मिलता

एसआईआर विरोध के साये में विधानसभा चुनाव

अवधेश कुमार

चार राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सबसे राहत देने वाला पक्ष इसका सीमित चरणों में संपन्न होना है। इन पांचों प्रदेशों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता 25 लाख इवीएम मशीनों के माध्यम से 824 विधानसभा सीटों के लिए 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मतार्धिकार का प्रयोग करने वाले हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में दो चरण में मतदान होंगे, जबकि शेष राज्यों में एक ही चरण में।

भारत की सुरक्षा व्यवस्था अब उस स्थिति में पहुंच गई है, जहां सुरक्षा बलों की कुछ ही टुकड़ियों को एक से दूसरी जगह चुनाव कराने के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं। अब भारत में चुनावी हिंसा न के बराबर है। पश्चिम बंगाल अस्थय डरावना अपवाद बना हुआ है, किंतु वहां हिंसा मतदान के दिन से पूर्व और बाद में ही ज्यादा होती है। इन प्रदेशों में केवल असम में भाजपा तथा पुडुचेरी में राजग की सरकार है। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में द्रमुक तथा केरल में एलडीएफ या वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है। इस चुनाव में विरोध, विकास, हिंदुत्व जैसे सामान्य मुद्दे तो हैं ही, एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका को विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति अपनाई है।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भी दिया जा चुका है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिला है। इस दृष्टि से देखें, जो यह चुनाव पिछले सारे चुनावों से भिन्न नजर आएगा। हालांकि, एसआईआर को लेकर जैसा विरोध और आरोप-प्रत्यारोप पश्चिम बंगाल से देखने को मिला है, उससे



लगता है कि शायद मतदाता सूची से सबसे ज्यादा नाम वहीं कटे हैं। पर सच यह है कि सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु से कटे हैं। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया में 74 लाख 07 हजार 207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 66 लाख लोगों के नाम कटे। केरल में आठ लाख, असम में केवल दो लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। असम में विशेष पुनरीक्षण काराया गया था। एसआईआर प्रक्रिया के बाद संशोधित मतदाता सूची से संपन्न बिहार चुनाव में राजग को एकपक्षीय बहुमत प्राप्त हुआ। राहुल गांधी द्वारा एसआईआर व चुनाव आयोग के विरुद्ध चलाए सारे अभियान जनता की दृष्टि में निष्फल साबित हुए। बेशक उनकी सभा में भीड़ आती रही, पर जमीन पर कहीं भी एसआईआर मतदाताओं के बीच मुद्दा नहीं बन सका। छोट्टी-मोट्टी पेशानियों और एकाध विवादों को छोड़कर आम लोगों को एसआईआर से कोई समस्या नहीं हुई।

मगर ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल इस समय ऐसा राज्य साबित हो रहा है, जिसके लिए कोई प्रक्रिया, विधान किसी तरह का सांविधानिक पद, केंद्र सरकार की योजनाएं आदि की स्वीकृति और अस्वीकृति ममता बनर्जी की मनमर्जी पर है। उन्होंने एसआईआर को इस तरह पेश किया, मानो यह वास्तविक मतदाताओं और

सकता है, जबकि 20% अभी अनिर्णय की स्थिति में है, यानी अनडिसाइडेड हैं। जहां तक सर्वाण वोटों के आकार की बात है तो पश्चिम बंगाल में हिंदू सर्वाण यानी ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य मतदाता, कुल मतदाताओं का करीब 15–20% हैं, जो मुख्यतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। भाजपा इन्हें सनानी एकता के जरिए साध रही है, और 2021 के विधानसभा चुनाव में 68% हिंदू वोट, जिनमें सर्वाण वोट प्रमुख रहे, भाजपा को मिले थे, जिससे वह 77 सीटें जीत पाई है।

जहां तक रणनीतिक महत्व की बात है तो भाजपा का 5% हिंदू वोट स्विंग फॉर्मूला सर्वाणों समेत हिंदू वोटों पर केंद्रित है, और टीएमसी से शिफ्ट का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि सर्वाण अनडिसाइडेड, मुस्लिम-टीएमसी समर्थन 23% हैं, इसलिए मुत्ता/ओबीसी वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि एसआईआर विवाद से मुत्ता वोट प्रभावित हो रहे, जो सर्वाण-केंद्रित भाजपा की रणनीति को कमजोर कर सकता है। वहीं टीएमसी सर्वाणों को ब्राह्मण वोट के रूप में लुभा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शॉडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हैं। लेकिन सर्वाणों पर भाजपा का पारंपरिक दबदबा भी बरकरार है। लिहाजा, सर्वाणों का वोट विभाजित होना तय है।

रही बात असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2026 विधानसभा चुनावों में सर्वाण वोटरों की भूमिका की तो यह राज्य-विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होगी। मुख्य रूप से ये भाजपा या एनडीए के पक्ष में काम कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक प्रभाव सीमित रहेगा। जहां तक असम की बात है तो यहां सर्वाण वोटरों में मुख्यतः ब्राह्मण-अग्रवाल वैश्य हैं, जो कुल मतदाताओं के 10–12% हैं और भाजपा के मजबूत समर्थक माने जाते हैं। यहां पर एनडीए की भाजपा ने राज्य की 89 सीटें जीत करके अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंत विश्वसरमा की लोकप्रियता के साथ लोग एकजूट हैं।

पश्चिम एशिया संकट और मोदी का संदेश

देवेश त्रिपाठी

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की महत्वपूर्ण बैठक के एक दिन बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत की आधिकारिक रणनीतिक स्थिति को स्पष्ट किया ही, इसने राष्ट्र की चिंताओं को ध्वनित करने के साथ ही समाधान की दिशा भी दिखाई है। पिछले महीने की 28 तारीख को ईरान पर अमेरिका व इस्त्राइल के संयुक्त हमलों से शुरू हुए इस संघर्ष ने होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग को प्रभावित किया है, जहां से दुनिया का 20 फीसदी ईंधन गुजरता है। प्रधानमंत्री का यह कहना निस्संदेह आश्चस्तकारी है कि अब हम पहले के 27 की जगह करीब 41 देशों से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। लेकिन, जिस तरह से युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसे देखते हुए मांग व आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने की चुनौती जरूर होगी। इसके अतिरिक्त, इस युद्ध ने चाबहार, भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारा (आईएनएसटीसी), जैसी पश्चिम एशिया में चल रही उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी संकट खड़ा कर दिया है, जिनसे भारत के हित जुड़े हैं। ऐसे में, भारत को अपने इन समझौतों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, जिनके सफल संचालन के लिए पश्चिम एशिया में शांति अनिवार्य शर्त है। उन वैकल्पिक मार्गों की ओर मुड़ने की भी जरूरत है, जो वैश्विक संकटों में भी हमें कमजोर न पड़ने दें। भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो प्रवासी भारतीयों की वापसी के आंकड़ों में भी दिखाता है। गौरतलब है कि करीब 3.75 लाख भारतीय अब तक



सुरक्षित लौट चुके हैं, जिनमें 700 से अधिक पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हालांकि, यह स्थिति दो मोर्चों पर चुनौती पेश कर सकती है। एक तो लौटने वालों के पुनर्वास की चुनौती होगी, और दूसरा इसके आर्थिक नुकसान भी हैं। भारत को हर वर्ष विदेश में रहने वाले भारतीयों से जितना रेंटिमेंस प्राप्त होता है, उसका करीब आधा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जहां करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं। इसके अलावा, जिस तेजी से देश ने डिजिटलीकरण को अपनाया है, उसे देखते हुए विदेशी सर्वरों पर निर्भरता एक राष्ट्रीय जोखिम भी पैदा कर सकती है। ऐसे में, प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने का निर्देश दिया है। जैसा कि कोरोना संकट के समय में भी देखा गया था, ऐसे वैश्विक संकटों का फायदा उठाने के लिए जमाखोरों के गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, जिन पर नियंत्रण जरूरी है। टूट का पांच दिन में समझौता करने का दावा मौजूदा स्थितियों में भले ही संशयपूर्ण हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि ऐसे वैश्विक संकटों में एकजुटता और रणनीतिक स्वायत्तता ही देश के सबसे अहम हथियार हैं।

अमरीका ईरान के खिलाफ युद्ध की ‘विडंबना’ को समझने में चूक गया

रख रमन

इतिहास में किसी भी युद्ध के बताए गए औचित्यों के पीछे, चाहे वे न्यायसंगत कारण हों, परमाणु खतरे हों, सच परिवर्तन हों, मूल सत्य एक ही है-संघर्ष हमेशा से संसाधनों की खोज रहा है। ईरान युद्ध महज इसका नवीनतम अध्याय है। गाजा और तेहरान पर एकतरफा बमबारी और एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष के अपहरण के बाद, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इसराईली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शायद खुद को यह यकीन दिला दिया था कि इसी तरह की रणनीति से ईरान को कुछ ही घंटों में कुचल दिया जाएगा। लेकिन 3 सप्ताह से चल रहे इस लगातार बढ़ते संघर्ष में, यह भ्रम बेरहमी से टूट गया है।

9 करोड़ से अधिक आबादी वाले ईरान की कुल आबादी अमरीका के युद्धक्षेत्रों वियतनाम, ईराक और अफगानिस्तान की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। इसके 40 लाख से अधिक नागरिक पश्चिमी देशों में रहते हैं, जो अब अपने वतन को जलते हुए देख रहे हैं। हजारों वर्षों की सभ्यतागत स्मृति धार इतने बड़े राष्ट्र को आसानी से अधीन नहीं किया जा सकता। अली खामेनेई की हत्या से ईरानी राज्य का पतन नहीं हुआ, इसने राज्य को विकेंद्रीकृत कर लिया है, जिससे किसी एकजुट शत्रु से भी अधिक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेतृत्वहीन आंदोलन से न तो बातचीत की जा सकती है, न ही उसे रोका जा सकता है और न ही उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

केंद्रीकृत सत्ता की जगह अराजकता ने नहीं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक कठोर शक्ति ने ले ली है- ‘खोने



को कुछ नहीं बचा’ का दृढ़ संकल्प। जो व्यक्ति एक ही दिन में अपने पूरे परिवार को खो देता है, वह बदला लेने की योजना बनाते समय सफलता की संभावनाओं का आकलन नहीं करता। किसी राष्ट्र के नेता, उसके परमाणु वैज्ञानिकों और उसके कमांडरों की बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लक्षित हत्या ने एक ऐसा द्वार खोल दिया है, जिसे बंद नहीं किया जा सकता। यदि अमरीकी और इसराईली सेनाएं ईरान में स्कूली छात्राओं और ज्यूरिख में वैज्ञानिकों को मार सकती हैं, तो किस सिद्धांत के आधार पर अमरीकी कंपनियों के सी.ई.ओ. ईरानी सेनाओं के निशाने से बाहर रहेंगे? यह नागरिकों को निशाना बनाने का तर्क नहीं है, एक चेतावनी है कि वैध लक्ष्यों का चुनाव एकतरफा नहीं होता।

अमरीका ने युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माता और प्रवर्तक के रूप में 8 दशक बिताए। ईरान में जो ध्वस्त किया जा रहा है, वह केवल एक शत्रुतापूर्ण शासन नहीं, बल्कि वह ढांचा ही ध्वस्त हो रहा है। तेहरान कुछ ऐसा समझता है जो इस अभियान के समर्थक नहीं समझते। एक ऐसा राष्ट्र, जिसने ईराक के साथ 8 साल का युद्ध झेला, रासायनिक हथियारों के खिलाफ लड़ाई

लड़ी और कठोर प्रतिबंधों का सामना किया, आसानी से टूटता नहीं। तीन सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता समय को समाचार चक्रों या अमरीकी चुनाव कार्यक्रमों के हिसाब से नहीं मापता। इतिहास महाशक्तियों द्वारा अभिमाना राष्टों को बलपूर्वक अधीन करने के प्रयासों के बारे में एक समान निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। वियतनाम, अफगानिस्तान और ईराक के उदाहरण लीजिए। सैन्य शक्ति को ‘लड़ने की इच्छाशक्ति’ समझ लेना बहुत भारी कीमत चुकाने का कारण बनता है।

हर युद्ध इस धारणा पर आधारित रहा है कि वह समाप्त हो जाएगा। इस धारणा के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। यह शत्रु को रियायत देने के लिए नहीं, बल्कि समझौते की पूर्व शर्त के रूप में होता है। पूर्ण मनमानी विजय नहीं, बल्कि हिंसा की स्थायी स्थिति पैदा करती है, जिससे आबादी कट्टरपंथी हो जाती है और हर रास्ता बंद हो जाता है। विडंबना यह है कि नियम-आधारित व्यवस्था की मौत से सबसे अधिक पीड़ित वही राष्ट्र होगा, जिसने इसे नष्ट किया है। अमरीका की शक्ति उन सहयोगियों के स्वेच्छिक सम्मान पर टिकी थी, जो मानते थे कि नियम वाशिंगटन सहित सभी पर लागू होते हैं। वह विध्वंसनीयता अब समाप्त हो चुकी है। संसाधनों के लिए हमेशा से संघर्ष होता रहा है। लेकिन किसी भी महाशक्ति के पास सबसे कीमती संसाधन तेल, क्षेत्र या परमाणु क्षमता नहीं है, बल्कि यह उस विश्व का विश्वास है, जिसका नेतृत्व वह करना चाहती है। इस संसाधनों को बलपूर्वक हारिसल नहीं किया जा सकता और एक बार खो जाने पर, किसी पर बमबारी करके इसे वापस नहीं पाया जा सकता।

पश्चिम एशिया में शक्ति प्रदर्शन की होड़, हो रहा पूरी दुनिया का नुकसान

देवेश त्रिपाठी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने और ऐसा न करने पर ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की चेतावनी को खारिज करते हुए तेहरान ने जिस तरह से इस्त्राइल पर मिसाइल हमलों का नया दौर शुरू किया है, उससे पश्चिम एशिया संघर्ष एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है।

ईरान के बिजली संयंत्रों को नेस्तनाबूद करने की अमेरिकी धमकी निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की कसौटी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऊर्जा संयंत्रों पर हमले सीधे तौर पर आम नागरिकों को प्रभावित करेंगे, जिससे बिजली, पानी, अस्पताल और संचार व्यवस्था इत्यादि सबकुछ टप हो सकता है। दूसरी तरफ, ईरान जो कर रहा है, वह भी कोई कम चिंताजनक नहीं है।

होर्मुज को बाधित कर उसने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में तो डाला ही है, इस्त्राइल के ऊर्जा स्रोतों और खाड़ी देशों पर हमला करके क्षेत्रीय युद्ध के वैश्विक संकट में तब्दील होने की आशंकाएं भी पैदा कर दी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता और कई सैन्य प्रमुखों के मारे जाने के बावजूद अमेरिकी चेतावनी पर ईरान की इस टिप्पणी से उसके तेवरों की ही झलक मिलती है कि अगर तेहरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, तो इसका खामियाजा पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा

संयंत्रों को भुगतना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू है, कूटनीति का हाशिये पर चले जाना। नाटो सहयोगियों की अनिच्छा, वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेद और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का तकरीबन गैरमौजूद दिखना दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस संकट से निपटने में किस कदर लाचार महसूस कर रही है।

भारत के लिए यह स्थिति खास तौर पर संवेदनशील है। होर्मुज में किसी भी किस्म की बाधा सीधे तौर पर देश में महंगाई और आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है और ऐसा होता दिख भी रहा है। देश में जारी गैस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सिलिंडरों की कालाबाजारी के बदस्तूर जारी रहने और महंगाई के बढ़ने से पश्चिम एशियाई संकट की आंच अब आम आदमी के घर तक पहुंच रही है, जो चिंताजनक है।

अब राष्ट्रपति ट्रंप भी इस युद्ध से बाहर निकलने की इच्छा जता रहे हैं, तो निश्चित ही उन्हें समझ लेना चाहिए कि सैन्य दबाव से हर संकट का समाधान नहीं हो सकता। अमेरिका व ईरान, दोनों को ही समझना होगा कि शक्ति प्रदर्शन की इस होड़ में अंततः नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। इसलिए यह समय है कि चेतावनी की भाषा छोड़कर संवाद की राह अपनाई जाए, वरना तो यह युद्ध फिलहाल थमने से रहा।

नवरात्रि में जानें किस राशि का दिन रहेगा खास

नवरात्रि के पावन अवसर पर 25 मार्च 2026 का दिन विशेष महत्व लेकर आया है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आएगा। जहां कुछ राशियों को करियर और व्यापार में उन्नति के संकेत मिलेंगे, वहीं कुछ को सतर्क रहकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। इस दिन रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा।

मेष राशि—मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। व्यापार में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव का माहौल बन सकता है।

वृषभ राशि—वृषभ राशि के लोगों के लिए यह दिन नए अवसरों के संकेत दे रहा है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और परिवार का सहयोग भी मिलेगा। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशि—मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव से बचना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी करीबी के व्यवहार से मन थोड़ा विचलित हो सकता है।

कर्क राशि—कर्क राशि के लोगों को इस दिन यात्रा से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय परेशानी बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना आवश्यक होगा। व्यापार में किसी पर अधिक भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है।

सिंह राशि—सिंह राशि के जातकों के लिए यह दिन सकारात्मकता लेकर आएगा। पुराने मित्रों से मुलाकात और घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक निर्णय भविष्य के लिए फायदेमंद



साबित हो सकते हैं।

कन्या राशि—कन्या राशि के लिए यह दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां थोड़ी चिंता बढ़ा सकती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा और किसी बड़े निर्णय से बचना उचित रहेगा।

तुला राशि—तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन रह सकता है। परिवार से जुड़ी किसी खबर से मन प्रभावित

हो सकता है। व्यापार में सावधानी बरतने की जरूरत है और साझेदारी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। परिवार का सहयोग आपको संभालने में मदद करेगा।

वृश्चिक राशि—वृश्चिक राशि के लिए यह दिन प्रगति के संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु राशि—धनु राशि के जातकों को इस दिन किसी भी नए कार्य में जल्दबाजी से बचना चाहिए। सोच-समझकर निर्णय लेना ही बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी।

मकर राशि—मकर राशि के लिए यह दिन स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित हो सकती है। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

कुंभ राशि—कुंभ राशि के जातकों को इस दिन अपने रिश्तों में संयम और समझदारी बनाए रखनी होगी। किसी की बातों में आकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बेहतर होगा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति को अच्छी तरह समझ लें। धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि—मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है और विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है।

चैत्र नवरात्र का सातवां दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां कालरात्रि की पूजा



चैत्र नवरात्र की सातवां दिन यानी सप्तमी तिथि बुधवार को है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। मां कालरात्रि की आराधना से भक्तों को शक्ति, साहस और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। वहीं, धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा, दान और नए कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत काल या विजय मुहूर्त में करना श्रेयस्कर होता है। हालांकि, राहुकाल और भद्रा के समय किसी भी शुभ काम से बचना चाहिए। बुधवार का पंचांग देखें तो सूर्योदय 6 बजकर 20 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 35 मिनट पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर

45 मिनट से 5 बजकर 33 मिनट तक है। सप्तमी पर अभिजित मुहूर्त तो नहीं लेकिन विजय मुहूर्त है, जो 2 बजकर 30 मिनट दोपहर से 3 बजकर 19 मिनट दोपहर तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 34 मिनट से 6 बजकर 57 मिनट तक और अमृत काल सुबह 9 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6 बजकर 20 मिनट से 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगा।

बुधवार को सप्तमी तिथि दोपहर 1 बजकर 50 मिनट तक है। उदयातिथि के अनुसार पूरे दिन सप्तमी का मान होगा। वहीं, नक्षत्र मृगशिरा शाम 5 बजकर 33 तक रहेगा।

25 मार्च को अशुभ समय पर विचार करें तो राहुकाल दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से 1 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा। यमगंड सुबह 7 बजकर 51 मिनट से सुबह 9 बजकर 23 मिनट तक और गुलिक काल सुबह 10 बजकर 55 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 3 मिनट से दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक प्रभावी रहेगा। साथ ही दोपहर 1 बजकर 50 मिनट से देर रात 12 बजकर 47 मिनट रात (25 मार्च) तक भद्रा प्रभावी रहेगा। इनमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं।

मंगल का कुंभ में उदय: 26 से बदलेगा ग्रहों का असर 6 राशियों को करियर और कारोबार में बड़ा लाभ



वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इसी क्रम में मंगल ग्रह का कुंभ राशि में उदय एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जा रही है। 26 मार्च 2026 से मंगल का यह परिवर्तन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। विशेष रूप से करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है।

मंगल उदय का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। जब यह ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। कुंभ राशि में मंगल का उदय मामलों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है।

मेष राशि—मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। मंगल का उदय आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में हो रहा है, जिससे आय और लाभ के अवसर बढ़ेंगे। लंबे समय से अटक हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सफलता के साथ-साथ सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

मिथुन राशि—मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। मंगल का उदय आपकी राशि से नौवें भाव में होगा, जो भाग्य का साथ बढ़ाएगा। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को नए अवसर मिलेंगे और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करने में सफलता मिलेगी।

सिंह राशि—सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय व्यापार में विस्तार और सफलता का रहेगा। मंगल का उदय आपकी राशि से सातवें भाव में हो रहा है, जिससे साझेदारी

और व्यवसाय में लाभ की स्थिति बन सकती है। सही निर्णय लेने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

मकर राशि—मकर राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन आर्थिक रूप से लाभकारी माना जा रहा है। मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में उदय हो रहा है, जिससे धन संचय के अवसर बनेंगे। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और संपत्ति से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी।

कुंभ राशि—कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का उदय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। यह आपकी राशि के लग्न भाव में हो रहा है, जिससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार में तेजी आएगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। नौकरी-पेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जिनमें विदेश से जुड़े अवसर भी शामिल हो सकते हैं।

मीन राशि—मीन राशि के लोगों के लिए यह समय आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। मंगल का उदय आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा, जिससे नए स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है। नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं और व्यापारियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भविष्य के लिए नई योजनाएं बन सकती हैं।

अंत में यह समझना आवश्यक है कि ज्योतिषीय गणनाएं आस्था और परंपराओं पर आधारित होती हैं, जिनका उद्देश्य जीवन में संभावित बदलावों के संकेत देना होता है।

घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए नवरात्रि में आजमा सकते हैं कपूर के प्राचीन उपाय

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च, गुरुवार से हो गई है। इन नौ दिनों का हिंदू धर्म में खास महत्व है, जिसमें मां दुर्गा के अलग-अलग 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान होता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, नवरात्रि के दिनों में पूजा के समय कपूर जलाने का खास महत्व होता है। वैसे तो शास्त्रों और ग्रंथों में नवरात्रि में कपूर के उपाय का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से ही इन दिनों में कपूर के विशेष उपाय करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है की इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है।

लौंग और कपूर का उपाय

ऐसी मान्यता है की मां भगवती को लौंग और कपूर की आहुति अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आप हवन के समय 48 लौंग के साथ 6 कपूर अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है की इस उपाय को करने से माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से घर-परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहता है। इसके साथ ही, कमल के फूल की पत्तियों पर मक्खन और मिश्री लगाकर मां को अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है।

घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने का उपाय



नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा में कपूर शामिल करने का खास महत्व होता है। अगर आप अपने कार्यों, नौकरी या व्यवसाय में रुकावटों का सामना कर रहे हैं तो नवरात्रि में कपूर का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए देवी की पूजा के समय एक दीये में कपूर और लौंग का जोड़ा जरूर रखें। साथ ही, दीपक प्रज्वलित करके मां की पूजा करें। शाम के समय घर में लौंग और कपूर जलाने से घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है।

घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय

कई बार घर में अचानक बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते घर-परिवार की शांति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। वहीं, हिंदू धर्म व शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसे में घर

विवाह में देरी के उपाय

अगर महिलाएं विवाह में देरी या बाधाओं का सामना कर रही हों, तो उन्हें ज्योतिषी की सलाह पर पीला नीलम धारण करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिति बेहतर हो सकती है। पीला नीलम गुरुवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है।

अगर कुंडली में शनि के चलते विवाह में देरी हो रही हो तो इसके लिए शनिवार के दिन शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे शनि की स्थिति बेहतर हो सकती है और विवाह की बाधाएं कम होने लगती हैं।

आप पीले रंग की वस्तुएं जैसे- हल्दी, चना दाल और पीले कपड़ों का दान भी किया जा सकता है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को बेहतर करने में भी मदद मिलती है।

शादी में देरी आने पर किसी कुशल ज्योतिषी से अपनी कुंडली के सातवें भाव, ग्रह दशा जरूर दिखाएं और उसी अनुसार समाह के दिनों पर उपाय करना चाहिए। इससे अशुभ प्रभावों में कमी आ सकती है।

सोनिया की तबीयत बिगड़ी राहुल ने रद्द किया केरल दौरा
नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए केरल का अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राहुल गांधी की जगह चुनाव वाले केरल का दौरा करेंगे। यह घटनाक्रम सोनिया गांधी के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन बाद सामने आया है। उनका वहां इलाज चल रहा है और डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जनवरी में भी उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष अजय स्वरूप ने उस समय कहा था कि विस्तृत चिकित्सा जांच में पता चला है कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव से सोनिया गांधी का ब्रॉकियाल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था। इसी वजह से डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी और आगे के इलाज के लिए भर्ती करने का फैसला किया था।

कमल हासन के फैसले पर छिड़ी बहस, डीएमके ने त्याग बताया

चेन्नई। द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने बुधवार को अभिनेता-राजनेता कमल हासन के आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव न लड़ने के

डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करने के फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक और निस्वार्थ बलिदान बताया। एएनआई से बात करते हुए अन्नादुरई ने कहा कि हमारे नेता एमके स्टालिन ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने इसे कमल हासन का ऐतिहासिक और निस्वार्थ बलिदान बताया है, जिन्होंने तमिलनाडु राज्य के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। डीएमके के सभी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता और नेता कमल हासन के इस नेक कदम के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिससे उनका कद और ऊंचा हुआ है। अन्नादुराई ने यह भी कहा कि कमल हासन एक महत्वपूर्ण नेता हैं और उनका प्रचार अभियान डीएमके पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

ओवैसी-कबीर दिखाएंगे बंगाल में अपने गठबंधन की ताकत

कोलकाता। जनता उज्जयन पार्टी (जेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन

ओवैसी के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन की पुष्टि की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी साझेदारी ही उनकी चुनावी रणनीति का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओवैसी के मार्गदर्शन में यह गठबंधन किया है और चुनाव प्रचार के दौरान वे उनके सुझावों का पालन करते रहेंगे। जनता उज्जयन पार्टी (जेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और एकजुट रहेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी और पिनारयी विजयन में सीक्रेट डील: कांग्रेस

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय

लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बीच गुप्त समझौते के आरोपों को दोहराया है। बुधवार (25 मार्च, 2026) को कोझिकोड में मीडिया को संबोधित करते हुए, कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नित्थला ने कहा कि केरल में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अलिखित राजनीतिक समझौता हुआ है। श्री चेन्नित्थला ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन 2021 के चुनावों के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य यूडीएफ को अलग-थलग करना और कांग्रेस-मुक्त भारत के सपने को साकार करना है। श्री चेन्नित्थला ने दावा किया कि 2021 में एनडीए के 69 सीटों पर वोट सीपीआई (एम) को हस्तांतरित हो गए थे।

एआईएडीएमके ने जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची

चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी, एआईएडीएमके ने बुधवार को 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख एडप्पाडी के.

पलानीस्वामी को उनके गृह क्षेत्र एडप्पाडी से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। राज्य में एनडीए का नेतृत्व कर रही इस पार्टी ने अपनी शुरुआती लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं को बरकरार रखा है, जिनमें के.पी. मुनुस्वामी, डिंडीगुल श्री. श्रीनिवासन और नाथम आर. विश्वनाथन शामिल हैं। पार्टी ने पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं जैसे एस.पी. वेलुमणि और पी. थंगामणि को भी क्रमशः थोंडामुथुर और कुमारपालयम से चुनाव मैदान में उतारा है। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही एआईएडीएमके ने अपनी पहली लिस्ट में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने अपने वफादुश्त और कद्दावर नेताओं को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है।

पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं भारत, ईरान मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक

नई दिल्ली। भारत ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में मध्यस्थता करने की पाकिस्तान की कोशिश पर निशाना साधा है।सूत्रों के मुताबिक, आज दिल्ली में हुई एक सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एन. जयशंकर ने पाकिस्तान को एक %दलाल राष्ट्र% कहकर उसकी निंदा की।

पाकिस्तान की तरह बिचौलिया नहीं भारत

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का गुप्तचर बना हुआ है। अमेरिका के हर संदेश को पाकिस्तान, ईरान तक पहुंचा रहा है। भारत के



विदेश मंत्री ने इसे ही लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूद एक सदस्य ने बताया कि विदेश मंत्री ने कहा, %भारत पाकिस्तान की तरह बिचौलिये की

भूमिका नहीं निभाएगा।

ईरान ने तुर्कतया पाकिस्तान का प्रस्ताव

अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और तुर्किए दोनों ही ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता पाकिस्तान या तुर्किए में हो सकती है।

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान और तुर्किए के अमेरिका की तरफ से भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान ने अमेरिका के सामने पांच शर्तें भी रखी हैं, जिनमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान को पूर्ण अधिकार मिलने की बात कही गई है।

केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मतदान के अधिकार छीन रहे हैं : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बुधवार को तीखा हमला करते हुए उन पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग “मतदान के अधिकार छीन रहे हैं।”

उन्होंने चेतावनी दी कि अगला कदम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करके नागरिकता छीनने का प्रयास हो सकता है। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से

कुछ समुदायों को चुनाव प्रक्रियाओं से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, “राजबंशियों के नाम एसआईआर के जरिए हटा दिए गए हैं।”

महिलाओं के नाम भी हटाए जा रहे हैं। अगर एसआईआर की वजह से मौतें होती हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा?” तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “निर्वाचन आयोग, भाजपा और केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रहे और मतदान के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज वे मतदान के अधिकार छीन रहे हैं; कल वे राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लाकर नागरिकता छीन लेंगे।” मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री



नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम

लिखा बिना बनर्जी ने जनसभा में उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे “यहां मौजूद सज्जन और दिल्ली में दोनों सज्जनों को विदा” करें।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत राज्य की जनता है। उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, “उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया है। अब मेरे पास सिर्फ हमारी जनता है।” बनर्जी से उत्तर बंगाल के

लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर निर्वाचन आयोग के छह साल पुराने दस्तावेज का हवाला देते हुए इसी तरह के आरोप लगाए थे।

इस दस्तावेज में कथित तौर पर भाजपा का कमल चिह्न अंकित था। उन्होंने कहा, “आप छुपकर क्यों खेल रहे हैं? खुलकर सामने आइए और मुकाबला करिए।” बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने साथ वकील ले जाने के लिए कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित असम में नामांकन रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, “मैं अपने उम्मीदवारों से नामांकन दाखिल करते समय वकीलों को साथ ले जाने के लिए कहूंगी। असम में कई नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। मुझे भाजपा और निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है।

भाजपा की हाईकमान चलाती है कठपुतली सरकार : गोगोई

गुवाहाटी। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने 25 मार्च को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए उस पर मुख्यमंत्री के पद का सम्मान न करने और दिल्ली से दूरस्थ रूप से राज्य सरकारों को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। गोगोई ने याद दिलाया कि पांच साल पहले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) से जुड़े आदिवासी नेता सरबानंद सोनोवाल को भाजपा को जीत दिलाने के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।

गोगोई ने कहा कि पांच साल पहले भाजपा में मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल थे, जो एएएसयू से जुड़े एक आदिवासी नेता थे। और उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने चुनाव जीता, सरकार बनाई और फिर उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बने क्योंकि उनका नाम पच्ची पर लिखा था। उन्होंने भाजपा पर नेतृत्व की भूमिकाओं को लेकर कुर्सी की खेल शैली अपनाते



का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री पद का उचित सम्मान नहीं करती। आगामी चुनावों में अपनी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर गोगोई ने कहा कि हमारा एकात्मत्र लक्ष्य कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनाना और असम की जनता को अधिकारों से वंचित नहीं है; यह पद पहले भी मेरा था और आज भी मेरा है। उन्होंने जनता के बदलाव के प्रति उत्साह को रेखांकित करते हुए कहा कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि वे देख सकते हैं कि उन्हें दस साल की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का एक ऐतिहासिक अवसर मिल रहा है। यहां की सरकार भय की राजनीति करती है, और इससे मुक्ति पाने का अवसर दिया जा रहा है, और हम जनता के साथ खड़े हैं। यह उत्साह बदलाव के लिए है। लोग एक तरह से नए असम की कल्पना कर रहे हैं।

स्टोल प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 92 रनों से शिकस्त दी

क्राइस्टचर्च। अमेलिया केर (105/ दो विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड की महिला टीम ने बुधवार को खेले गये पांचवें टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 92 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली हैं। अमेलिया केर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया।

195 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण के आगे बेबस नजर आए। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नो विकेट पर 102 रन ही बना सकी और मुकाबला 92 रनों से हार गई। एनरी डकर्सन ने सर्वाधिक 23 रनों की पारी खेली। उनके अलावा सुने लूस ने (13) और कायला रेनेके ने (10) रनों का योगदान दिया। अयाबोंगा खाका (12) रन बनाकर नाबाद रही। शेष सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।

न्यूजीलैंड के लिए लिया तहहू ने तीन विकेट लिए। सोफी डिविइन और अमेलिया केर को दो-दो विकेट मिले। नेंसी पटेल और फ्लोरा डेवनशायर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 194 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहला विकेट 9 रन के स्कोर गिरने के बाद अंतराल पर अपने विकेट गंवाए। हालांकि इस दौरान अमेलिया केर एक छोर थामे विस्फोटक बल्लेबाजी करती रही। जॉर्जिया प्लिमार ने (27) और ब्रूक हैलिडे (26) रनों का योगदान दिया। अमेलिया केर ने 55 गेंदों में 19 चौके और एक छक्का उड़ते हुए 105 रनों की पारी खेली।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1205 अंक उछला निफ्टी 23306 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार (25 मार्च) को लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में मजबूती के साथ बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बयान के चलते बाजार में खरीदारी देखने को मिली। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंक चढ़कर 74,652.01 पर खुला। सोमवार को यह 74,068 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 75,849 अंक तक चढ़ गया था। अंत में 1205.00 अंक या 1.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,273.45 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 23 हजार का लेवल पर बंद 23,064 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 23,465 अंक के इंट्रा-डे हाई लेवल तक गया। अंत में 394.05 अंक या 1.72 फीसदी की बढ़त लेकर 23,306 पर बंद हुआ।

35 नहीं, 25 दिन में ही मिलेगा शहरों में गैस सिलिंडर

नई दिल्ली। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा में बदलाव को लेकर फैल रही खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा व्यवस्था ही लागू है। मंत्रालय के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समयसीमा लागू की गई है। सरकार ने इन दावों को भ्रामक और गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी रीफिल बुकिंग की मौजूदा समयसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, जो सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू है।

एलपीजी संकट : पाइप लाइन बिखाने के नियमों में बड़ा बदलाव

नईदिल्ली। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की ऊर्जा व्यवस्था को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आए इस नए नियम का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि अब गैस पाइपलाइन बिखाने के काम में कोई सरकारी अड़ंगा या देरी न हो सके। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में बड़ी परियोजनाएं सालों लटक रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी विभाग ने तय समय सीमा के भीतर पाइपलाइन बिखाने की अनुमति नहीं दी, तो उसे स्वचालित मंजूरी मान लिया जाएगा। यानी, अब फाइलों के रुकने से काम नहीं रुकेगा। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होने से अलग-अलग राज्यों के चक्कर काटने की झंझट भी खत्म हो जाएगी।

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय तेल कंपनी की अपील

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से काम कर रही है। बीपीसीएल के अनुसार, भारत पेट्रोल और डीजल का नेट एक्सपोर्टर है और कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल व एडीएफ का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह परिचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हथियारों और तेल के भंडार की लड़ाई: ईरान युद्ध कब रुकेगा, किसी को नहीं पता

देवांशु दत्ता

छोटी लड़ाइयां सामरिक कुशलता से जीती जा सकती हैं, लेकिन लंबी लड़ाइयां आमतौर पर रसद और औद्योगिक क्षमता से जीती जाती हैं। ईरान युद्ध अब अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अब इसकी जीत और हार इस बात पर टिकी हो सकती है कि दोनों पक्षों में से किसके पास किस तरह के शस्त्रों का भंडार बचा है तथा वैश्विक तेल और गैस के भंडार की क्या स्थिति है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन का भंडार है जबकि अमेरिका और इजरायल के गठबंधन के पास मिसाइल इंटरसेप्टर हैं। ईरान का शस्त्रागार सस्ता, बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाला और कमतर तकनीक का है। इसके मुकाबले मिसाइल इंटरसेप्टर कहीं अधिक महंगे हैं। अमेरिका और इजरायल को हर बार 15,000 से

20,000 डॉलर की लागत वाले ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराने पर लगभग 30 से 40 लाख डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह, पैट्रियट मिसाइल बनाने में शाहिद ड्रोन बनाने की तुलना में कहीं अधिक समय लगता है।

इजरायल की वायु रक्षा प्रणालियां, प्रसिद्ध आयरन डोम (और कम दूरी की नई आयरन बीम), हवाई खतरों की पहचान करने और उन्हें नाकाम करने में उत्कृष्ट हैं। लेकिन अगर इजरायल के पास इंटरसेप्टर की कमी हो जाती है, तो ईरानी हवाई हमलों से निपटना व्यावहारिक रूप से मुश्किल होगा।

वर्तमान युद्ध के 26 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान पश्चिम एशिया के विभिन्न स्थानों को निशाना बना रहा है और दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका ईरान के ठिकानों पर बमबारी जारी रखे हुए हैं।

अगर ईरान सैन्य साजो-सामान भंडार



खत्म हो जाता है, तो इजरायल और अमेरिका को फायदा होगा। अगर इजरायल और अमेरिका का भंडार खत्म हो जाता है, तो ईरान को फायदा होगा। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों से उसकी उत्पादन क्षमता भले ही कम हो गई हो, लेकिन उसके ड्रोन इतनी हल्की तकनीक वाले हैं कि इन्हें कार सर्विस सेंटर्स में भी बनाया जा सकता है, इसलिए ईरान शायद इनका उत्पादन जारी रख सकता है, भले ही कम मात्रा में हो।

अन्य महत्वपूर्ण भंडार कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। होर्मुज स्ट्रेट के

बंद रहने से हर सप्ताह विश्व की सालाना तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 0.5 फीसदी बाजार से बाहर हो जाता है। ऊर्जा ढांचे पर हमलों के कारण कतर को रास लाफान स्थित अपने विशाल गैस टर्मिनल को बंद करना पड़ा है। इसे इतना नुकसान पहुंचा है कि इसकी मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं और 20 अरब डॉलर से अधिक का खर्च आ सकता है।

स्ट्रेट बंद होने के कारण सऊदी अरब, कुवैत और इराक की अधिकांश क्षमता भी ठप पड़ी है। ईरान के खर्ग द्वीप संयंत्र और दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र में अन्य ऊर्जा ढांचे (जो कतर के साथ साझा हैं) पर अमेरिकी-इजरायली हमलों ने तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने की ईरान की क्षमता को भी कम कर दिया है।

युद्ध समाप्त होने के बाद भी संयंत्रों की मरम्मत और उत्पादन को फिर से शुरू करने

में कई महीने या साल लग जाएंगे। यूक्रेन युद्ध की भू-राजनीति और वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, अप्रभावित क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने में भी समय लग सकता है। फारस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में बाब अल-मंडेब स्ट्रेट का वैकल्पिक मार्ग बनाने में भी कई साल लगेंगे और भारी लागत आएगी। भू-राजनीति के जानकारों को याद होगा कि बाब अल-मंडेब भी एक ऐसा ही अवरोध बिंदु है जहां हतियों ने कई बार लाल सागर में यातायात बाधित किया है। हतियों को इसे बंद करने से रोकने के लिए अमेरिका को 2025 में युद्धविराम समझौते पर सहमत होना पड़ा था।

कुल मिलाकर, ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनिश्चितता के लिए बाजार से बाहर हो सकता है। इस दौरान, दुनिया कच्चे तेल और गैस के भंडारों का उपयोग करेगी।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों की नवरात्रि भी हुई समृद्ध: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। किसानों की खुशियों भरी होली के बाद अब भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए भी यह नवरात्रि समृद्धि और आत्मविश्वास का संदेश लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार की योजनाएं अब सीधे जनजीवन में परिवर्तन का आधार बनती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 4 लाख 95 हजार 965 भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 495



करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि श्रम और सम्मान को सशक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत

मिली राशि ने उनके आत्मनिर्भरता के संकल्प को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता राशि भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जा रही है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। सरकार किसानों से किए गए वादे के अनुरूप 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक: डॉ. कुसमरिया



रायपुर। मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए व्यापक सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिसे सांख्यिकीय विभाग को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा देशभर के पिछड़ा वर्ग आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर साझा मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की जाए।

■ पिछड़ा वर्ग के सामाजिक विसंगतियों को दूर करना- छ.ग.पि. वर्ग आयोग अध्यक्ष निषाद

छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आयोग के कार्यों की समीक्षा की तथा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल विभिन्न जातियों की सामाजिक स्थिति, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विविध रूप में देखने को मिलती है। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों को दूर करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भाजपा जो कहती है उसे करती भी है : शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी में किए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत बुधवार को प्रदेश के 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रदेश की साय सरकार ने 495 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक हितग्राहियों को 10 हजार प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। आज साय सरकार में प्रदेश का हर वर्ग युवा, महिला, किसान सभी खुशहाल है। आदिवासी अंचल के लोग भी केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा



संचालित की जा रही सभी योजनाओं का लाभ ले रहे है। युवाओं के कौशल विकास के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं, महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, प्रदेश के किसान आज अपनी उपज का उचित कीमत प्राप्त कर रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्रहक भी तेंदूपत्ता के संग्रहण के माध्यम से सरकार की योजनाओं से सशक्त बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होगा। इनके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों के वंदेस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सब कार्य तेजी से हो रहे हैं।

महापौर ने कचरा कलेक्शन के लिए 11 इलेक्ट्रानिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी



रायपुर। नगर पालिक निगम द्वारा राजधानी शहर रायपुर की कचरा संग्रहण प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया गया। भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को 28 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया है और ये 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। इसमें अब प्रत्येक नागरिक, संस्थान को गीला, सूखा, सेनेटरी एवं स्पेशल केयर वेस्ट चार श्रेणियों में कचरा अलग

करना (पृथक्करण) अनिवार्य है। आज कुल 11 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शुभारंभ रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे द्वारा सभापति सूर्यकान्त राठौड़, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर एमआरसी सदस्य सर्व महेंद्र सोडियार, मनोज वर्मा, अवतार भारती बागल भोलाराम साहू, अमर गिदवानी, नंदकिशोर साहू खेम कुमार सेन, संजना संतोष हियाल, सरिता आकाश दुबे, सुमन अशोक

मानवता की सेवा के लिए रेडक्रॉस सोसाइटी से जुड़ने का आह्वान

रायपुर। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिला आयुष अधिकारी डॉ. स्वाति रावत के आग्रह पर एक दिन में 39 नए सदस्य बने जिसमें डॉ. सावित्री पाणीग्रही, डॉ. गीता राजपूत, डॉ. नेहा साहू, डॉ. हेमकुमार राठौर, डॉ. अरुंधती देवांगन, डॉ. पूर्णिमा राजपूत, डॉ. सोनल शर्मा, डॉ. इंदु विश्वकर्मा, डॉ. सविता साहू, डॉ. अशोक बांधे, डॉ. राजलक्ष्मी शर्मा, डॉ. सोमा शुक्ला, डॉ. स्वाति अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने रेडक्रॉस सोसाइटी में वार्षिक सदस्य के रूप में सदस्यता ली। जिला आयुष अधिकारी डॉ. स्वाति रावत ने सदस्यों की सदस्यता राशि जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को दी।



इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एक स्वतंत्र मानव समाजसेवी संस्था है, जो आपदा एवं संकट की परिस्थितियों में पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पित है। संस्था द्वारा भूकंप, आग, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तथा रक्तदान शिविरों का नियमित आयोजन किया जाता है। संस्था से जुड़ने के लिए विभिन्न श्रेणियों में सदस्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संरक्षक सदस्य के लिए 25,000 रुपये, उप संरक्षक सदस्य के लिए 12,000 रुपये, आजीवन सदस्य के लिए 1,000 रुपये तथा वार्षिक सदस्यता के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस अवसर पर रेडक्रॉस के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों से संस्था से जुड़कर मानव सेवा में योगदान देने का आह्वान किया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

गृह मंत्री नक्सलवाद खात्मे की औपचारिक घोषणा कर रहे है : बैज

रायपुर। गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा प्रदेश में नक्सलवाद की समाप्ति के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्या गृह मंत्री का यह बयान इस बात की औपचारिक घोषणा माना जाय कि प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है? नक्सलवाद समाप्ति के लिए सरकार ने क्या पैमाना माना था और उनमें से कितने पैमाने पूरे हो चुके है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। क्या केंद्र सरकार भी इस बात की घोषणा करेगी की छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो चुका है? नक्सलवाद एक संवेदनशील विषय है। प्रदेश के गृह मंत्री यदि राज्य से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर रहे है तो उन्हें इस संदर्भ में प्रदेश की जनता को विश्वास भी दिलाना होगा केवल कोरी बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। गृह मंत्री इस बात की गारंटी लेंगे कि अब बस्तर में किसी निर्दोष का खून नहीं बहेगा? अब बस्तर का आम आदिवासी मारा नहीं जाएगा, सिर्फ बयानबाजी नहीं सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन आना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यदि नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो राज्य सरकार ने अभी तक बस्तर से कितने सुर्क्षाबलों के कैप हटाना शुरू किया? कितने सुरक्षा बलों की बस्तर से वापसी करना शुरू किया।



अफीम की खेती पर सरकार लीपापोती कर रही है : शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अफीम की खेती को लेकर सरकार के द्वारा जिला कलेक्टरों से क्लीन चिट लेकर जारी करना इस बात को साबित करता है कि सरकार अफीम और अन्य मादक पदार्थों की खेती पर लीपापोती करना चाहती है, वह केवल दिखावे की कार्यवाही कर रही है। सरकार बताये कि जिन कलेक्टरों ने अपने जिले में अफीम की खेती नहीं होने का दावा कर रहे है, यदि उनके जिले में अफीम आदि खेती होना पाई जायेगी तो सरकार उन पर कार्यवाही करेगी? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिन जिलों में अफीम की खेती के प्रकरण सामने आये है क्या सरकार वहां पर किसी अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित कर कार्यवाही करेगी या फिर वहां पर सिर्फ खेती करने वाले पर कार्यवाही की खानापूर्ति की जायेगी? खुलेआम अफीम की खेती क्या बिना सरकारी अमले के संरक्षण के संभव है? क्या इस खेती के पीछे राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण नहीं था? अभी तक प्रदेश के अलग-अलग कोनों में अफीम की खेती पकड़ाई है। अफीम की खेती का खुलासा जनता ने किया है। जनता ने पुलिस से शिकायत किया, पुलिस और राजस्व अमला क्या कर रहा था।



खेलो इंडिया ट्राईबल गेम्स आयोजन में भारी गड़बड़ी: ठाकुर

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राईबल गेम्स आयोजन में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार में खेलो इंडिया के तहत आयोजित ट्राईबल गेम्स भी जम्मूरी की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।आयोजन स्थल में खिलाड़ियों को भरपेट भोजन के लिए तरसना पड़ा।मेन्स के अनुसार खिलाड़ियों को जो भोजन मिलना था, वो मिला नहीं बल्कि भरपेट भोजन एवं पानी के लिए भी खिलाड़ी तरस रहे थे। प्रदेश में ट्राईबल गेम्स में भाग लेने देश के किये राज्यो से खिलाड़ी आये है, उनके सामने भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार उजागर हो गई। ट्राईबल गेम के आयोजन के पहले बालोद में जम्मूरी के आयोजन में भारी भ्रष्टाचार हुआ था जिसकी जांच भी नहीं कराई गई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री ट्राईबल गेम्स के आयोजन में शामिल हुए उन्होंने भोजन के स्टाल का निरीक्षण का निरीक्षण किये तब तक खिलाड़ियों को भोजन में परीसे मेन्स के अनुसार पनीर की सब्जी मौजूद था, जैसे मंत्री निकले स्टाल से पनीर की सब्जी एवं अन्य भोजन सामग्री गायब हो गई खिलाड़ी पनीर ढूंढते रहे है, स्थिति यह रही कि खिलाड़ियों को भोजन करने भी वाद विवाद का सामना करना पड़ा।



सरकार का भ्रष्टाचार निचले पैमाने तक पहुंचा: वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सोशल ऑडिट में 151 करोड़ की गड़बड़ी बताता है की सरकार का भ्रष्टाचार निचले पैमाने तक पहुंच गया है। पूरे प्रदेश में 13861 गड़बड़ियां सामने आना इस बात का प्रमाण है कि सरकार के संरक्षण में पंचायतों के विकास कार्य का पैसे में बंदरबांट हुआ है। इस पूरी गड़बड़ी में सत्तारूढ़ दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल है। सरकार के हर काम में कमीशनखोरी जोरो पर है। पंचायत विभाग के अधिकारी पंचायतों के फंड आबंटन में पहले अपना कमीशन लेते है, उसके बाद आबंटन जारी करते है। इसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते है, बिना काम के पैसा आहरण हो जाता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार का वित्तीय स्थिति इतनी खास्ताहाल है कि वह पंचायतों को उनके मलभूत का पैसा तो दे नहीं पा रही है जो थोड़ी बहुत राशि सरकार ने जारी किया है वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बंद हो चुके है। सरकार के पास विकास कार्य करवाने के लिये फंड ही नहीं है। दो साल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक भी ग्राम पंचायत में सड़क एवं नाली का निर्माण नहीं कराया गया है।



सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का खुला खेल: तिवारी

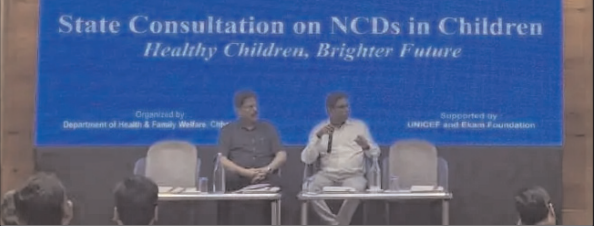
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और सहकारिता विभाग पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तानाशाही का गंभीर आरोप लगाते हुये कहा कि विभाग के मंत्री, सचिव और पंजीयक की तिकड़ी ने सहकारिता के मूल सिद्धांतों की हत्या कर दी है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के लगभग 850 कर्मचारियों के वैध वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता तिवारी ने आरोप लगाते हुये कहा कि, प्रदेश सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के भाई दिनेश कश्यप जगदलपुर जिला सहकारी बैंक के (प्राधिकृत) अध्यक्ष है, उन्होने कथित चंदा उगाही कर कर्मचारियों के 6 वर्षों के रुके हुए वेतन को पंजीयक के मार्गदर्शन में आनन-फानन में बहाल कर दिया है। वहीं, रायपुर के 850 कर्मचारियों के मामले में विभाग जानबूझकर अड़ो लगा रहा है। क्या नियम केवल चंदा देने वालों के लिए बदले जाते हैं। कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता तिवारी ने रायपुर के कर्मचारी जब माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से अपना हक जीत गए।



स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के तकनीकी सहयोग से राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन

बच्चों में गैर-संचारी रोगों पर राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित

रायपुर। बच्चों में बढ़ते गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), विशेषकर बाल मधुमेह, सिकल सेल रोग एवं जन्मजात हृदय रोग की रोकथाम, शीघ्र पहचान तथा प्रभावी प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायपुर में संजीव कुमार झा (संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन किया गया। इस परामर्श का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना, बहु-विभागीय समन्वय को बढ़ावा देना तथा गुणवत्तापूर्ण उपचार एवं सुदृढ़ रेफरल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में



एनसीडी की वर्तमान स्थिति, प्रमुख चुनौतियों एवं भावी प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने शीघ्र पहचान, दवाओं की सतत उपलब्धता, उपचार अनुपालन तथा मजबूत रेफरल तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। सिकल सेल रोग प्रबंधन हेतु जशपुर मॉडल को एक प्रभावी

एवं अनुकरणीय पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। पैनल चर्चाओं में बाल मधुमेह एवं सिकल सेल रोग के समग्र प्रबंधन, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सामुदायिक सहयोग तथा सामाजिक कलंक को कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। समूह कार्य के माध्यम से प्रतिभागियों ने

स्क्रीनिंग बढ़ाने, उपचार अनुपालन सुधारने तथा सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में एम्स रायपुर एवं पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के विशेषज्ञों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा संघ एवं भारतीय शिशु रोग अकादमी के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का सफल संचालन यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. जगदेव सिंह के नेतृत्व में, एकम फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। तकनीकी सत्रों में डॉ. खैरराज सोनवानी (उप संचालक,

सिकल सेल), डॉ. वी.आर. भगत एवं सुबोध धर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सलाहकार उपस्थित रहे। परामर्श में ट्राइबल वेलफेयर विभाग, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधियों की सहभागिता से बहु-विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ किया गया। सहयोगी संस्थाओं की ओर से विश्व स्वास्थ्य संगठन, संगवारी, क्लिंटन फाउंडेशन, एनएससीओ, प्रतिनिधि जुवेनाइल डायबिटीज तथा पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय योगदान दिया।

प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023-430 पदों पर चयन सूची जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती-2023 की प्रक्रिया के बाद अंतिम: अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कुल 430 पदों पर भर्ती के लिए जारी इस प्रक्रिया में एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 4 अगस्त 2023 को हुई थी, जब रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें 1,28,685 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त 2025 को किया गया, जिसमें 1,12,792 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा परिणाम 18 सितंबर



2025 को घोषित किया गया, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 8 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 23 फरवरी 2026 तक चली। सत्यापन के आधार पर 2106 अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया। इसके बाद 13 मार्च से 23 मार्च 2026 तक अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति मंगाई गई। कुल 53 अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, जिनका निराकरण कर 24

मार्च 2026 को अंतिम सूची तैयार की गई। अंततः 25 मार्च 2026 को जारी अंतिम चयन सूची के अनुसार 430 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें विभिन्न वर्गों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए भी 30 पद आरक्षित रखे गए हैं, जिनमें 15 पद हर (वन लेग) और 15 पद ।।। (हियरिंग हैंडिकैप्ड) श्रेणी के लिए निर्धारित हैं। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 मार्च और 2 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रदेश के 285 महाविद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार पदस्थ किया जाएगा। नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी किए जाने की जानकारी विभाग ने दी है।